तृतीय माला, खंड 55, अंक 51 शनिवार, 30 अप्रेल, 1966/10 वैशाख, 1888 (शक)

Third Series, Vol. LV, No. 51 Saturday, April 30, 1966/Vaisakha 10, 1888 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 55 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 51—शनिवार, 30 अप्रैल, 1966/10 वैशाख, 1888 (शक)

No. 51—*Saturday, April* 30, 1966/*Vaisakha* 10, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*अ० सु० प्र० संख्या S. N. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
24	ताम्बरम क्षेत्र में विस्फोट	Explosions in Tambaram Area .	7723–26
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी का समाचार	Reported Acute Scarcity of Kerosene Oil	7726–30
	नियम समिति --	Rules Committee—	
	द्वितीय प्रतिवेदन	Second Report	7730
	विशेषाधिकार समिति---	Committee of Privileges—	
	पांचवा तथा छठवाँ प्रतिवेदन	Fifth and Sixth Report .	7730–31
	वित्त विधेयक ---	Finance Bill, —	
	विचार के लिए प्रस्ताव--	Motion to consider—	
	श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar .	7731–32
	श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	7732–33
	श्री हनुमन्तैय्या	Shri Hanumanthaiya .	7733–35
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	7735–37
	श्री रामनाथन चेट्टियार	Shri R. Ramanathan Chettiar	7737–39
	श्री सुमत प्रसाद	Shri Sumat Prasad	7739–40
	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	7740–41

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—57 Lok Sabha/66

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री लखमू भवानी	Shri Lakhmu Bhawani	7741
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	7741–42
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen .	7742
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee .	7742–43
श्री पाराशर	Shri Parashar . . .	7743–45
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendra Nath Dwivedy	7745–47
श्री चं० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharya .	7747–48
श्री बाल कृष्ण सिंह	Shri Bal Krishna Singh	7748
श्री यल्लमन्दा रेड्डी	Shri Yallamanda Reddy	7749
श्री ओझा	Shri Oza .	7749–51
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	7751–52
श्री अरुणाचलम	Shri Arunachalam	7752–53
श्री लहटन चौधरी	Shri Lahtan Chaudhry	7753

लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, 30 अप्रैल, 1966/10 वैशाख, 1888 (शक)

Saturday, April 30, 1966/Vaisakha 10, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ताम्बरम क्षेत्र में विस्फोट

+

अ० सु० प्र० 24. श्री बाल कृष्णन :
श्री मुथिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताम्बरम क्षेत्र में वायु सेना की गतिविधियों के कारण हाल ही में कई बार विस्फोट हुए;

(ख) क्या ये विस्फोट हवाई अड्डा क्षत्र में बड़ी बड़ी इमारतों को गिराने के लिये हो रहे हैं;

(ग) क्या ये विस्फोट भूकम्प आने के कारण हुए थे; और

(घ) क्या इनका कारण जानने के लिये कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : ताम्बरम क्षेत्र में वायु सेना की गतिविधियों के कारण अथवा हवाई अड्डा क्षेत्र में बड़ी बडी इमारतों को गिराने के कारण कोई विस्फोट नहीं हुए हैं ।

(ग) और (घ) : वेधशाला महानिदेशालय, नई दिल्ली के भूकम्प विज्ञान के निदेशक, ताम्बरम गये और उन्होंने मामले की जांच की । उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आधार पर मद्रास सरकार ने जनता को आश्वासन दिया है कि पिछले कुछ सप्ताहों में ताम्बरम तथा उसक आसपास

महसूस किये गये झटके साधारण किस्म के भूकम्प के झटको के कारण आये थे और इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है। राज्य सरकार ताम्बरम में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के एक विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन कराने तथा घटना का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने के लिये ताम्बरम में ऋतु विज्ञान विभाग के अधिकारी को नियुक्त करने के लिये भी कार्यवाही कर रही है ।

श्री बालकृष्णन : क्या यह सच नहीं है कि मामले की जांच करने के लिये वहां भेजे गये वेधशाला के निदेशक ने यह स्वीकार किया है कि ये विस्फोट कुछ समय पूर्व उस क्षेत्र में बमों तथा पुराने हथियारों को नष्ट करने के कारण किये गये थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : वास्तम में इस विशेष मामले में 24 मार्च और 17 अप्रैल के बीच भूकम्प के झटके आये थे। वायुसेना द्वारा परीक्षण अथवा प्रयोग के तौर पर अन्तिम विस्फोट 3 मार्च, 1966 को किया गया था, अर्थात् बहुत पहले जब शिक्षण कार्य के लिये एक एक करके 25 पौंड के बमों को नष्ट किया गया था। बाद में जिन बमों का विस्फोट किया गया था उनमें 5 पौंड से कम विस्फोटक पदार्थ थे और उन्हें स्वीकृत स्थान पर साफ मौसम में उस समय किया गया था जब हवा की गति 10 नॉट थी। सबसे निकट की नागरिक आबादी 4 मील से अधिक दूरी पर थी।

अत: इसका वायु सेना के प्रयोगों अथवा इस प्रकार की किसी बात से सम्बन्ध नहीं है। इस अवधि के दौरान वायुसेना ने न तो कोई परीक्षण ही किये थे और न कोई विस्फोट ही किया था। मैं बता चुका हूं कि अन्तिम परीक्षण 3 मार्च को किया गया था। इस क्षेत्र में ऐसे परीक्षण कई वर्षों से किये जा रहे हैं।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन भूकम्प के झटकों के समय हुई आवाज तोप चलने के धमाके अथवा जमीन के अन्दर किये गये विस्फोटों के धमाके के समान थी। अत: लोगों का यह सोचना स्वाभाविक था कि ये धमाके वायुसेना द्वारा किये गये परीक्षणों के कारण हुए। किन्तु वायु सेना का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। ये झटके उस बीच आये भूकम्प के कारण हुए थे ।

श्री मुथिया : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीका के कोलोराडो क्षेत्र में, जिसमें कई सौ वर्षों से भूकम्प नहीं आये थे, मानवीय कारणों से, अर्थात सेना द्वारा गहरे कुएं खोदे जाने तथा उनमें हजारों गैलन अपशिष्ट पानी भरे जाने के कारण, हाल में बार बार भूकम्प आये थे, क्या मंत्री महोदय यह समझते है कि मानवीय कारणों से, कम से कम परोक्ष रूप से, ताम्बरम में झटके आये थे ?

श्री अ० म० थामस : ये झटके मानवीय कारणों से नहीं आये । ये प्राकृतिक थे ।

श्री नाथ पाई : मुझे प्रसन्नता है कि इसे सभा में अल्प-सूचना प्रश्न के रूप में लिया गया है क्योंकि मैंने इस मामले को ध्यान दिलाने वाली सूचना के अन्तर्गत उठाने का प्रयत्न किया था।

मंत्री महोदय ने बताया है कि भूकम्प के कारण ये झटके आये थे। हम यह नहीं जान पाये कि हमें भूतपूर्व मंत्रियों के कथन पर विश्वास करना चाहिये या वर्तमान मंत्रियों के कथन पर। भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री ति० त० कृष्णमाचारी, ने इन विस्फोटों के बारे में व्यक्त विचारों के बारे में इस प्रकार कहा है :—

"भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री ति० त० कृष्णमाचारी को तो ताम्बरम में वायुसेना स्टेशन के बहुत निकट रहते है, पूरा विश्वास है कि यह विस्फोट स्टेशन के अन्दर हुआ। वह विश्वास नहीं करते हैं कि यह किसी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया। इन विस्फोटों से उस क्षेत्र की इमारतों को खतरा है......

"श्री ति० त० कृष्णमाचारी तथा ताम्बरम निवासियों ने वायुसेना की इन गतिविधियों के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट किया है और श्री कृष्णमाचारी ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये और जिन गतिविधियों से जनता की सुरक्षा को खतरा है, उन्हें समाप्त किया जाये।"

एक ओर तो भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय बारबार कहते हैं कि ये विस्फोट वायुसेना स्टेशन के अन्दर हुए और दूसरी ओर मंत्री महोदय इस से इन्कार कर रहे हैं।

जब कि दक्षिण भारत के सभी समाचार पत्रों में इस विवाद के बारे में प्रकाशित हो रहा है, क्या यह वांछनीय नहीं है कि मंत्रालय इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये पहल करता? प्रक्रिया के कारण हमारे प्रयत्न निष्फल हो गये। सरकार विलम्ब क्यों करती है? दक्षिण भारत के प्रमुख समाचार पत्र 'हिन्दू' में प्रतिदिन इस बारे में प्रथम पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित होते हैं। मंत्री महोदय को पहले ही वक्तव्य देना चाहिये था।

श्री अ० म० थामस: मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है। प्रमुख व्यक्ति ने भी भूल से इस आवाज को तोप की आवाज अथवा भूमि के अन्दर विस्फोट की आवाज समझा होगा। मैंने भी भूतपूर्व वित्त मंत्री के 15 अथवा 16 अप्रैल के वक्तव्य को पढ़ा है। दूसरे दिन वायु सेना के अधिकारियों ने उसका खण्डन किया था। बाद में 18 अप्रैल को मद्रास सरकार के जन सम्पर्क विभाग में इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया कि ये झटके किस प्रकार आये तथा इनका वायु सेना से कतई कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैंने इस सम्बन्ध में तकनीकी व्यक्तियों से बातचीत की थी और उन्होंने मुझे बताया कि सभी विवर्तनिक भूकम्प चट्टानों के परस्पर रगड़ के कारण आते हैं। इससे एक आवाज निकलती है जो प्रेक्षकों के अनुसार तोप की अथवा भूमि के नीचे किये गये विस्फोटों की आवाज के समान होती है। अतः इस सम्बन्ध में भ्रम हो जाना विचित्र बात नहीं है।

श्री कण्डप्पन: मंत्री महोदय का यह कहना कि भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार इनसे कोई हानि नहीं होगी, गलत है क्योंकि वहां के लोग भयभीत हैं। ये झटके इतने हल्के नहीं थे जितना कि उन्हें बताया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस सम्बन्ध में आगे जांच तथा अध्ययन करके जनता को इस बात के लिये सहमत कराने के लिये तैयार है कि यह अधिक खतरनाक नहीं है?

श्री अ० म० थामस: यह कतई खतरनाक नहीं है। ये झटके दूर के स्थानों पर रिकार्ड नहीं किये गये हैं। इससे यह पता लगता है कि ये बहुत ही साधारण थे। इन में से कुछ झटके जोकि—भौतिकी वेधशाला, कोडाइकनल, ऋतु विज्ञान कार्यालय, पूना में लगे अच्छे किस्म के भूकम्प लेखों तथा अणुशक्ति आयोग द्वारा लगाये गये अच्छे किस्म के भूकम्प लेखी द्वारा रिकार्ड किये गये। ये बहुत हल्के थे। यह 2 और तीन के बीच में था। 4 से 6 तक यह खतरनाक हो जाता है। मैं नहीं कहता कि ये झटके हानिरहित था। किन्तु चिन्ता की कोई बात नहीं है। इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: क्या उसी क्षेत्र में बार बार भूकम्प आये हैं और क्या इन झटकों का वायुसेना द्वारा पहले किये गये विस्फोटों से कोई सम्बन्ध है और यदि हां, तो क्या इस पहलू की जांच की गई है?

श्री अ० म० थामस: जी हां, इसका वायुसेना से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि जो विस्फोट किये गये हैं उनमें विस्फोटक पदार्थ लगभग पांच पौंड थे। पांच पौंड विस्फोटक पदार्थों से ये झटके नहीं आ सकते हैं। यह क्षेत्र आबादी से 4 मील दूर है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पहले के विस्फोटों का भी इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कण्डप्पन : श्री कृष्णमाचारी ने कहा था कि खिड़की और किवाड़ झनझना गये थे।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें सरकार से जानकारी लेनी है, न कि श्री कृष्णमाचारी से।

श्री स० मो० बनर्जी : वक्तव्य में कहा गया है कि इसका वायुसेना के परीक्षणों से कोई सम्बन्ध नहीं था। क्या यह सच है कि एक विस्फोट से सी प्रकार की घर्घर की आवाज सुनाई दी थी और आपने मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये कहा था? किन्तु इसकी जानकारी नहीं दी गई। क्या दिल्ली में यह भूकम्प के कारण हुआ था या किसी विस्फोट के कारण?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का दिल्ली से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : मंत्री महोदय ने बताया है कि कई भूकम्प लेखी द्वारा रिकार्ड की गई जानकारी के अनुसार यह भूकम्प का झटका था। सरकार ने इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी जिससे भय और भ्रम पैदा नहीं होता? इस सम्बन्ध में भूतपूर्व मंत्री को भी वक्तव्य देना पड़ा।

श्री अ० म० थामस : इस समाचार के प्रकाशित होते ही भारतीय वायुसेना ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी और मद्रास सरकार ने उसकी घोषणा कर दी थी। यह कहना गलत है कि हमने समाचारों की ओर ध्यान नहीं दिया था।

अविलम्बनिय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी का समाचार

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : श्रीमान, मैं पैट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"देश में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी का समाचार"।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि 21 फरवरी, 1966 को मैंने मिट्टी के तेल की सप्लाई एवं वितरण के बारे में एक संक्षिप्त विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। जैसा कि उस विवरण पत्र में बताया गया था हमने मार्च, 1966 से आगे के लिये राज्य-वार कोटा निर्धारित किया और इन कोटों को पूरा करने के लिये प्रत्येक कम्पनी के सप्लाई का अंश भी। घटिया मिट्टी के तेल के कुछ दुरूपयोग का समंजन (adjustments) करने के बाद 1964 को खपत के आकड़ों के आधार पर इन कोटों को निर्धारित किया गया। वर्ष 1965 से सम्बन्धित आंकड़ों को नहीं लिया गया था क्योंकि कई कारणों से यह एक सामान्य वर्ष नहीं था। हमने राज्य सरकारों को इन कोटों को जिला-वार कोटों में समधिक करने को कहा और य भी कहा कि वे देख कि सम्पूर्ण जन संख्या में उचित वितरण किया गया है।

26 मार्च, 1966 को मने राज्य सरकारों के सिविल सप्लाईज मंत्रियों का भी क सम्मेलन बुलाया; जिसमें मिट्टी के तेल और दूसरे तेल उत्पादों की सप्लाई एवं वितरण से सम्बन्धित समस्याओं पर बातचीत की गई। इस सम्मेलन में एक सुझाव दिया गया कि 75 प्रतिशत आवंटन

(allocation) पिछली खपत और 25 प्रतिशत आवंटन जन-संख्या के आधार पर होना चाहिये। मैंने इस सुझाव पर विचार करने का तय किया। इस के साथ साथ देश में विद्यमान शोधन क्षमता से मिट्टी के तेल का उत्पादन बढाने एवं मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्राओं का आयात करने के लिये कदम उठाये गये।

हमने यह जानने के लिये भी कदम उठा कि मार्च और अप्रैल 1966 के महीनों में विभिन्न राज्यों को निर्धारित किये गये कोटे उन राज्यों में पहुंच गये। इस के बावजूद कुछ क्षेत्रों में कमियां हुई जैसे कि हाल ही में बम्बई नगर में। कुछ राज्यों ने आग्रह भी किया है कि उन के मासिक आवंटनों में वृद्धि की जाये। मार्च में ही पश्चिमी बंगाल के कोटे में 2500 मीटरी टन की वृद्धि की गई। अर्थात् 20,500 मीटरी टन से 23,000 मीटरी टन।

रक्षा व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, पंजाब के कोटे में अप्रैल, 1966 के लिये 1200 मीटरी टन की वृद्धि की गई अर्थात 8,800 मीटरी टन से 10,000 मीटरी टन। उत्तर प्रदेश के कोटे में अप्रैल, 1966 के लिये 500 मीटरी टन की वृद्धि की गई अर्थात् 16,700 मीटरी टन से 17,200 मीटरी टन। अप्रैल, 1966 के लगभग मध्य से उड़ीसा के कोटे को 3,200 मीटरी टन से 4,200 मीटरी टन तक बढा दिया गया।

सदन को बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि हम आन्तरिक उत्पादों एवं आयातों से समस्त उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए निम्न राज्यों के बारे में मई, 1966 से आवंटन बढाने में समर्थ हुए हैं। यह इस प्रकार है :—

राज्य	अप्रैल 1966 के लिये कोटा	मई 1966 के लिये कोटा	वृद्धि
1. आन्ध्र प्रदेश . . .	12,600	13,600	1,000
2. बिहार . .	12,500	13,500	1,000
3. गुजरात . .	15,100	15,850	750
4. केरल	8,100	8,600	500
5. मैसूर	9,200	9,700	500
6. राजस्थान .	5,300	5,800	500
7. उत्तर प्रदेश	17,200	18,200	1,000

इन बढ़े हुए कोटों की घोषणा के साथ हम राज्य सरकारों को यह भी लिख रहे है कि वे अपने वितरण प्रबन्धों में सुधार करें ताकि उनके क्षेत्रों के अन्दर किसी जगह भी कमी न पैदा होने पावे।

श्री नारायण दांडेकर : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष, 1965 को किए विशेष कारणों से मिट्टी के तेल के वितरण के लिये कोई आधार नहीं बनाया गया था; तथा महाराष्ट्र और बृहद बम्बई के लिये कोटा क्यों नहीं बढ़ाया गया है और क्या इसका कारण इण्डियन आयल कम्पनी द्वारा वितरण नहीं कर सकता है?

श्री अलगेशन : 1965 संकट का वर्ष था इस लिये 1964 को पिछले उपभोग का आधार बनाया गया है। महाराष्ट्र के कोटे में वृद्धि न करने का कारण यह है कि उसका औसत उपभोग केवल 37,868 टन है जबकि उसका कोटा 46,200 टन था। इण्डियन आयल कम्पनी अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से तेल का वितरण कर रही है।

Shri Yaspal Singh (Kairana) : I would like to know the action taken by the Government against profiteers, State-wise.

श्री अलगेशन : राज्य सरकारों ने तेल के उचित वितरण के लिये विभिन्न पग उठाये हैं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मंत्री महोदय ने कहा कि बम्बई में प्रति व्यक्ति कोटा 10 किलो लिटर होना चाहिये परन्तु बम्बई में लोगों को तेल के लिये मीलों लम्बी पंक्ति में खड़ा रहना पड़ता है। क्या महाराष्ट्र सरकार को तेल देने के बाद मंत्री महोदय का दायित्व समाप्त हो जाता है।

श्री अलगेशन : यह ठीक है कि वहां लम्बी पंक्तियां होती थी और यदि वितरण ठीक प्रकार से होता तो लोगों को एसी कठिनाई न होती। महाराष्ट्र सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि अब स्थिति ठीक हो गई है और वह मिट्टी के तेल के उचित वितरण के लिये व्यापारियों पर निगरानी रख रही है। मुझ यह सूचना कल ही मिली है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : क्या यह सच नहीं है कि 1965 में पहले के साधनों से आयात सीमित कर दिया गया और सोवियत संघ से तेल के आयात का एकाधिकार प्राप्त करने के कारण 1965 में समूची कठिनाई आरम्भ हुई?

श्री अलगेशन : यह ठीक है कि विदेशी मुद्रा की भारी कमी के कारण पुरानी तेल कम्पनीयों से 1965 में मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीज़ल का आयात बन्द कर दिया था परन्तु उसके स्थान पर रूस और रुमानिया जसे रुपयों में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से आयात किया जाने लगा था। मांग में वृद्धि के कारण हम ने सोवियत संघ से अधिक तेल देने को कहा है और उन्होंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : तीन दिन पूर्व गुजरात के समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि अहमदाबाद नगर में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है। क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि क्या वितरण करने वाले सम्भरण नहीं कर पाये हैं अथवा सरकार ने वितरण के आदेश समय पर जारी नहीं किये हैं।

श्री अलगेशन : वितरण का दायित्व राज्य सरकारों पर है। अहमदाबाद में कुछ कठिनाइयां थीं। मई के लिए सम्भरण में हमने 750 टन की वृद्धि कर दी है। कम्पानयां समय पर तेल का सम्भरण करती रही हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether the Government have tried to ascertain the market price from non-official sources ? In the villages kerosene is being sold at the rate of Rs. 1·50 or 2·00 per bottle.

श्री अलगेशन : हमें गैर-सरकारी सूत्रो से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैंने स्वयं इस बात की शिकायत सुनी ह कि कुछ राज्यों में मिट्टी का तेल 1 रुपया अथवा 1.50 रुपये प्रति बोतल मिल रहा है। हम राज्य सरकारों को वितरण प्रबन्ध ठीक करने तथा पर्याप्त मात्रा में तेल प्राप्त करने के लिय कह रहे हैं।

Shri Bagri (Hissar) : If the Minister has come to the conclusion that more price is being charged for the kerosene oil, has he taken any steps apart from issuing instructions ? May I know whether the Minister is aware that urban areas are supplied larger quantity of kerosene in comparison to rural areas ? If so, whether the Ministry has taken any action with regard to that.

श्री अलगेशन : हमने कई आदेश जारी किये हैं जिनके द्वारा राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में कार्यवाही करने की शक्ति, व्यापार विनियमन और मूल्य निर्धारित तथा लागू करने की शक्ति दी गई है ।

Shri Kishan Pattanayak (Sambalpur) : May I know whether the recommendation of Oil Prices Enquiry Committee regarding putting an end to high salaries and regional expences in private Companies has been accepted ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

Shri Kishan Pattanayak : You are putting an end to commonsense.

Mr. Speaker : You must withdraw those words.

Shri Kishan Pattanayak : If you compel me to withdraw those words, I will rather prefer to leave the House.

(इसके पश्चात् श्री किशन पटनायक सभा से उठ कर चले गये ।)

(Shri Kishan Pattanayak then left the house.)

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी): क्या यह सच है कि 1964 में निर्धारित कोटे का आधार ठीक नहीं है और कुछ राज्यों की, विशेष रूप मे आन्ध्र प्रदेश की यह वास्तविक शिकायत है कि कोटा जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये । यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री अलगेशन : जनसंख्या का आधार ठीक नहीं है क्योंकि विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिस्थितियां हैं । कुछ राज्यों में ग्रामों में विद्युतीकरण, कोयला और जलाने की लकड़ी आदि अधिक है जिससे मिट्टी के तेल का उपयोग कम हो जाता है । हमने इस मामले में आन्ध्र प्रदेश को सन्तुष्ट कर दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह सिद्ध हो गया है कि वितरण व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है । इसके साथ ही गैर-सरकारी तेल कम्पनीयां अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा वितरण व्यवस्था में सुधार करने की बजाय हजारों कर्मचारियों को फालतू घोषित कर रही हैं । सरकार ने श्री आर० एल० मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है । क्या यह सच है कि विदेशी तेल कम्पनियों ने सरकार को उस समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित न करने के लिये कहा है ? यदि हां, तो सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि वे कम्पनीयां उचित व्यवहार करें ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य छंटनी का मामला अप्रत्यक्ष रूप में लाना चाहते हैं । लगभग सभी राज्यों में सम्भरण व्यवस्था ठीक है और संतोषजनक है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते है कि छंटनी से वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री महेश्वर नायक (मयूरभंज) : उड़ीसा में मयूरभंज जिले में तेल 40 रुपये प्रति टीन बिक रहा है। वितरण व्यवस्था में इतना अधिक दोष है अथवा सम्भरण में त्रुटि है।

श्री अलगेशन : उड़ीसा में अप्रल के मध्य में ही कोटा 1,000 मीटरिक टन बढ़ा दिया गया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : उत्तरों से मालूम होता है कि तेल की कमी केवल पश्चिमी बंगाल में ही नहीं बल्कि समूचे देश में है। म जानना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है।

Shri Madhu Limaye : I want to say something with regard to the question of privilege.

Mr. Speaker : You should write to me.

नियम समिति
RULES COMMITTEE

दूसरा प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

पांचवां और छठा प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : म विशेषाधिकार समिति का पांचवां और छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : इस सम्बन्ध में मैंने नियम 377 के अन्तर्गत एक वक्तव्य देने की सूचना दी थी। प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार किये जाने और उसके स्वीकृत होने के बाद मने एक विमत्ति टिप्पण प्रस्तुत किया था परन्तु बाद में समिति ने मेरी अनुपस्थिति में मेरे विमत्ति टिप्पण का खंडन करने के लिए प्रतिवेदन में एक अनुबन्ध जोड़ने का निश्चय किया। उसके बाद 28 अप्रैल को मैंने एक परिशिष्ट दिया जिसमें कहा गया कि (क) अनुबन्ध नयमों के अनुसार सभा में प्रस्तुत किय जाने वाले प्रतिवेदन के साथ जोड़ा नहीं जा सकता तथा (ख) इस टिप्पण में दिये गये तक सभा को भ्रम में डालने के लिये रखे गये हैं।

विशेषाधिकार समिति ने 29 अप्रैल को मेरी अनुपस्थिति में निर्णय किया कि मेरा परिशिष्ट समिति ने प्रतिवेदन में शामिल करने को कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सभा के नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे समिति मेरे इस परिशिष्ट को प्रतिवेदन में शामिल न करे। समिति का ऐसा निर्णय उसके एक सदस्य के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप है।

श्री पाराशर (शिवपुरी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह व्यक्तव्य नहीं दिया जा सकता। यह व्रक्तव्य वास्तव में नियम 377 के अन्तगत नहीं आता है। दूसरे माननीय सदस्य विशेषाधिकार समिति के सदस्य है। उन्हें पहले यह मामला समिति में उठाना चाहिये था और उसके बाद उन्हें वक्तव्य देने के लिये सभापति से अनुमति लेनी चाहिये। उन्होंने ऐसा न करके विशेषाधिकार समिति की अनुमति के बिना यह मामला सभा में उठाया है। यह समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपूर सिंह ने मुझे लिखा था कि वह इस प्रश्न को सभा में उठाना चाहते हैं। उनक आग्रह करने पर मने अनुमति दे दी। यदि वह सभा में उपस्थित नहीं थे तो इसमें समिति का क्या दोष है। समिति जब भी चाहे, कोई निर्णय ले सकती है।

कपूर सिंह : वह निर्णय सभा के नियमों के अन्तर्गत होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये अध्यक्ष से अपील की जानी चाहिये थी। सभा में खड़े हो कर समिति की आलोचना करना उचित नहीं है जब तक कि समिति के प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा न हो।

वित्त विधेयक—जारी

FINANCE BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री शचीन्द्र चौधरी द्वारा 29 अप्रैल, 1966 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ की जायेगी, अर्थात :—

"कि वित्तीय वर्ष, 1966–67 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : 1960–61 की तुलना में 1965-66 में जो अतिरिक्त राष्ट्रीय आय हुई थी उसका 42 प्रतिशत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को मिला है। 1960–61 की तुलना में 1965–66 में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा करों के रूप में राष्ट्रीय आय से निकाली गई अतिरिक्त राशि 1960–61 की तुलना में 1965–66 में जो अतिरिक्त राष्ट्रीय आय हुई उसका 26 प्रतिशत अंश थी। कर व्यक्तियों द्वारा दिये जाते हैं न कि राष्ट्रीय आय द्वारा इसलिये कर लगाते समय प्रतिव्यक्ति आय को ध्यान में रखना चाहिये न कि राष्ट्रीय आय को। प्रतिव्यक्ति आय कर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त कराधान 1960–61 की तुलना में 1965–66 की अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति आय का 30 प्रतिशत था। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री की यह बात बिल्कुल असंगत है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय पर केवल 15 प्रतिशत कर लगा हुआ है जबकि पांच वर्ष पूर्व यह 9.6 प्रतिशत था। ये आंकड़े गलत है। वास्तविक आंकड़े वही है जो मैंने अभी बताये हैं।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले पांच वर्षों में थोक के मूल्यों में 30 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है जोकि बहुत अधिक है। इस वृद्धि से तथा वार्षिकी जमा खातों के अतिरिक्त बोझ के फलस्वरूप लोगों की खर्च करने योग्य आय में काफी कमी हुई है। इसलिये जनता के प्रत्येक स्तर पर बचत की मात्रा में तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई जाने वाली पूंजी तथा इसके परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण में भारी कमी हुई है। पिछले 12 महिमों में 382 करोड रुपये के अतिरिक्त कर लगाये गये है।

[श्री नारायण दांडेकर]

वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण तथा उसके उत्तर में कहा था कि उनके पास यही विकल्प है कि यदि विकास योजनाओं को वर्तमान रूप में क्रियान्वित करना है तो हमें अवश्य ही अधिक कर लगाने पड़ेंगे अन्यथा विकास कार्य बन्द करने पड़ेंगे। परन्तु मेरे विचार में यह एक भ्रामक बात है क्योंकि एक तीसरा विकल्प भी है कि व्यय पर ध्यान दिया जाये और यह समझा जाये कि विभिन्न प्रकार की मितव्ययता की पर्याप्त गुंजाइश है।

पिछले 15 वर्षों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के खर्च में बहुत वृद्धि हुई है। 1950–51 में केन्द्रीय सरकार का खर्च 510 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों का खर्च 400 करोड़ रुपये था। इस प्रकार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों का कुल 910 करोड़ रुपये खर्च था। परन्तु 1965–66 में यह खर्च बढ़कर 5300 करोड़ रुपये हो गया है। इसलिये मेरा कहना है कि इसमें मितव्ययता की काफी गुंजाइश है।

आयोजित विकास पर 2225 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। यहां मैं यह बता देना चाहता हूं कि बोकारो इस्पात कारखाने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुत बोझ पड़ेगा और वह बोझ सहन नहीं हो सकेगा। इसलिये बोकारो इस्पात परियोजना को समाप्त कर दिया जाना चहिये। राष्ट्रीय आय का लगभग पांचवा भाग गैर-योजना तथा गैर-विकास के कार्यों में लगाया जाता है। इससे निस्सन्देह 300--500 करोड़ रुपये की कटौती की जा सकती हैं। अब समय आ गया है जबकि हमें तथा कांग्रेस दल को अपने दल के हितों की बजाय देश के हितों की ओर ध्यान देना चाहिये।

पिछले वर्ष अप्रत्यक्ष करों तथा उत्पादन-शुल्क में वृद्धि विशिष्ट वचनों पर की गई थी परन्तु इन वचनों को पूरा नहीं किया गया है। पहला वचन सरकारी व्यय में बचत करना था। दूसरा वचन यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रुपये का मूल्य बनाये रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। आज समूचे विश्व में रुपये का मूल्य बिल्कुल ही नहीं है। इसलिये इन सीमा शुल्कों तथा उत्पादन शुल्कों के जारी रहने का समर्थन नहीं किया जा सकता।

आयकर तथा निगम कर के प्रति व्यक्ति आय पर बोझ के कारण उनकी दरों में वृद्धि का मैं विरोध करता हूं। बढ़ी हुई कीमतों तथा दूसरे कारणों से औद्योगिक कारखाने अपने विस्तार के लिये न तो स्वयं आय कर रहे है और न ही उनको जनता से ऋण मिल रहा है।

एक के बाद दूसरे संशोधनों के कारण आय कर बहुत ही जटिल हो गया है। 1961 से लेकर 1965 तक आय कर अधिनियम में कई बार संशोधन हो चुका है। वित्त मंत्री इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पहले आय कर में संशोधन बहुत कम हुआ करते थे तथा बहुत सोच-विचार के बाद किये जाते थे। परन्तु अब तो संशोधन एक आम बात हो गई है। इसलिये उनका अध्ययन करना एक कठिन कार्य है।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : My hon. friend Shri Dandekar has tried to prove in his speech through various figures which he has presented that during the last fifteen years tax burden has increased on the public and that Government take away major portion of the National income through these taxes. There is no doubt that the burden of taxation has been on the increase after every Plan. In this connection I would like to say that our is a under-developed country both in the field of Science and technology. We are hundred years behind in the industrial field as campared to other countries. It is, therefore, necessary that we should make some sacrifices even at the cost of some hardships so that country's development and progress is not retarted. We have to tighten our belts for the sake of the prosperity of the future generations. The Congress Government and party realised this thing and took the responsibi-

lity of imposing of taxes and making tne country prosperous. It snould also not be forgotten tnat the people have borne this burden with fartitude and this is evident by the return of the Congress Party to power in Centre as well as in States successively ın the three general elections.

There could not be two opinions about tne necessity of reducing the Government expenditure both at the Centre and State. This expenditure is constantly on the increase. In spite of the vaıious efforts, Government have not been able to achieve any success in this regard. All the non-development expenditure should be reduced to the minimum.

I think our tax system has been reshaped on a reshaped on a scientific system. The expenditure tax is a part of a scientific taxation system. The Finance Minister has, himself admitted that it would be a scund principle to replace tne income tax increasingly by a tax on expenditure so that maximum incentive is provided for saving. The expenditure tax should not, therefore, have been abolished.

Mostly there are two types of taxes in our country *i.e.* direct and indirect taxes. Most of the indirect taxes are passed on to tne common man. Thus, the ıeal burden of tne excise dutıes fell on tne poor masses. Inspıte of the various measures taken by Government prices of the commodities are constantly increasing. In the circumstances, I think that the increase ın excise duty on sugar is wholly unjustified. Measures should be taken to mop up the income of the rich people, which has increased dispıoportionately, through direct taxes such as estate duty, wealth tax, gift tax, etc.

I congratulate the hon. Mınister for givıng some concessıons to Handloom and other small scale ındustrıes. But I would also like to say that we have become too much dependent upon foreign technology, machinery, experts and raw mateıial. If we are to learn anything from tne recent Indo-Pakistan conflict that we must give up this dependence as far as possible and we should try to develop our own research, impıove our technology so that our industry could develop according to tne needs and conditions of our own country. While doing all that we must keep in mind that we have got surplus of man-power.

At present a serious problem of rising prıces is facing the country. It is true that Government take steps to check it. But still there is a need to adopt more measures in this regard.

We should also be very cautious about the foreign loans which we have incurred in sucn proportion as might endanger our economy.

Atnongh we have accepted and adopted a mixed economy yet we should expand the public sector as much as possible . It will be in tne interest of our country. But at the same time, in the present stage of our development we cannot ignore the private sector also. There have been many complaints from the private sector regarding the adveıse effect of the present tax structure which retarded capital formation. In my view a commission should be appointed to go thoroughly in the question as to the fields to be covered by the public and private sectors.

श्री हनुमन्तैय्या (बंगलौर-नगर) : मंत्री गण संसदीय कार्यवाही की ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं देते हैं। सभी ओर से संसदीय संस्थाओं की क्रियान्विति पर आक्षेप हो रहा है। इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि लोग संसदीय संस्थाओं तथा उनके प्रतिनिधिओं से एक प्रकार

[श्री हनुमन्तैय्या]

की घृणा करने लगेंगे। वास्तव में यही हो रहा है। जहां कहीं भी संसद सदस्यों अथवा विधान सभाओं के सदस्यों का उल्लेख होता है लोग हंसी उड़ाते हैं। इस स्थिति के लिये हमारे नेता ही जिम्मेदार है। संसद सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर मंत्री गम्भीरता से विचार नहीं करते हैं। संसद का महत्व बहुत कम हो गया है। यह एक बहुत गलत संकेत है।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश वापस नहीं लिया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश को तीन उद्देश्यों को सम्मुख रखकर पास किया गया था। वे तीन उद्देश्य थे सोने के मूल्य को कम करना, सोने के तस्कर व्यापार को रोकना तथा सोने के मूल्य को कम करके अन्तर्राष्ट्रिय बाजार के मूल्यों तक लाना। ये तीनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं। सभी लोगों का यह मत है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश लाभकारी नहीं है और न ही इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कोइ लाभ हो रहा है।

कोई भी स्वर्ण नियंत्रण आदेश के बारे में गम्भीर नहीं है। सभी पुरानी तरह से सोने के जेवरात बना रहे हैं, सोने का तस्कर व्यापार किया जा रहा है और यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं और उनके सिद्धान्तों का हमें पालन करना चाहिये। उनका पहला सिद्धान्त यह था कि कहने और करने में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। स्वर्ण नियंत्रण आदेश की कार्यान्विति का जहां तक संबंध है हम इस सिद्धान्त का पालन नहीं कर रहे हैं। आज सरकारी तंत्र को लोग हिकारत की नजर से देखते हैं मैंने एक दो दिन पहले श्री मोरारजी देसाई से, जिन्होंने इस स्वर्ण नियंत्रण आदेश को जारी किया था, विस्तार से बातचीत की थी। उनकी भी यही राय है कि जिस तरह से इस आदेश को क्रियान्वित किया जा रहा है उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। उनकी राय है कि ऐसो अवस्था में तो इसे पूणतया समाप्त कर दिया जाना ही बहतर है। मैं यह सब श्री मोरारजी देसाई की पूर्व अनुमति से ही कह रहा हूं।

यह केवल उनकी या मेरी राय का ही प्रश्न नहीं है। यदि इस सभा के माननीय सदस्यों की बिना किसी दबाव के राय ली जाये तो वे इसे समाप्त किये जाने के पक्ष में ही राय देंगे।

अफ्रीका तथा एशिया के देशों में इस सभा को एक आदर्श लोकतंत्रीय संस्था माना जाता है। इसलिये हमें यहां पर अच्छी परम्परायें कायम करनी चाहिये। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि कुछ मंत्री गण नहीं तो लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं और न ही अपने दल की इच्छा के अनुसार। सभा में कोरम बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है परन्तु सभा की शोभा तथा प्रतिष्ठा बनाये रखना विरोधी दलों के हाथ में है।

मंत्रियों में एक अन्य कमी यह है कि उनमें नये विचारों का अभाव है विशेष कर वित्तीय नीति के बारे में। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय विश्व में इन दिनों मुद्रा पद्धति में सुधार का प्रश्न खूब जोरों पर है। सोने का फिर महत्व बढ़ने जा रहा है और इसे पुनः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का आधार बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। हमारे लिये बुद्धिमत्ता की बात यही होगी कि देश में अधिक से अधिक सोना जमा किया जाये। चाहे यह सोना सरकारी खजाने में हो या लोगों के पास हो, यह हमारी राष्ट्रीय सम्पति होगा। अन्तर्राष्ट्रीय दर की तुलना में अपना कृत्रिम दर चालू करने की बजाय वित्त मंत्रालय को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिये जिससे हमारे देश में अधिक से अधिक सोना आ सके। इससे सोने का तस्कर व्यापार भी स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बढ़ती जा रही महंगाई है। हमारी स्थिति इंडोनेशिया जैसी होने जा रही है और पैसे की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि कम से कम एक-दो वर्ष तक केवल उन मदों पर ही धन खर्च किया जाना चाहिये जिनसे उत्पादन में वृद्धि हो। अन्यथा मुद्रास्फीति इतनी बढ़ जायेगी कि हमारे सभी प्रयत्न असफल हो जायेंगे और इस देश से लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पश्चिम) : पिछले दो मास में हुई गम्भीर घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं देश में अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति के बारे में ही अपने विचार व्यक्त करूंगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

15 वर्ष के आयोजन के बाद आज पहली बार हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जब कि हमारी अगली योजना की रूपरेखा भारत की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद में नहीं बल्कि वाशिंगटन में तयार की जायगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।

वाशिंग्टन के आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए समाचारों से पता चलता है कि वाइस-प्रजीडन्ट हम्फरी ने हमारे योजना मंत्री से पूछा है कि भारत योजना बद्ध आर्थिक विकास क्यों करना चाहता है। हम आज इस स्थिति में पहुंच गये हैं।

चाहे कोई कितना ही क्यों न कहे कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था तथा विश्व बैंक अमरीकी सरकार की संस्थाएं नहीं है परन्तु सब जानते ह कि उनपर अमरीका का पूर्ण नियंत्रण है। सब जानते हैं कि उन्होंने क्या शर्तें पेश की हैं और यह बात भी स्पष्ट है कि किस तरीके से वे हम पर दबाव डालना चाहते ह। दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय करार करने की स्वतंत्रता देने की बजाय हमें विश्व बैंक से सहायता लेने के लिये बाध्य किया जा रहा है। यदि विश्व बैंक और अम ीका ने अपने ढंग से ही सहायता देनी है तो उससे जिस प्रकार का विकास होगा उसका एक ठोस उदाहरण अभी हाल ही में हमारे सामने था, अर्थात उर्वरक करार। उसकी शर्तें बहुत ही अपमानजनक है और हमारे औद्योगिक नीति संकल्प के बिल्कुल विरुद्ध हैं। कुछ समय पहले "इंडियन एक्सप्रेस" में यह समाचार निकला था कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने सरकारी क्षत्र में चार या पांच उवरक कारखाने स्थापित करने के लिये प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दिये जाने का एक प्रस्ताव रखा था। हमें केवल तकनीकी जानकारी चाहिये। क्योंकि हमारे देश में नापथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ऐसा कोई प्रस्ताव था। और उसे क्यों अस्वीकार किया गया। अपने कच्चे माल से सरकारी क्षत्र में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर सकते हैं और हमें ऐसी शर्तें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी जो हमारे औद्योगिक नीति संकल्प के सर्वथा विरुद्ध हैं। यदि आर्थिक कठिनाई के कारण सरकार कभी कभी अवांछनीय करार करने के लिये बाध्य हो जाती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी आर्थिक आवश्यकता थी जिसके कारण सरकार यह भारत-अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान करार करने के लिये बाध्य हो गई है। आर्थिक आवश्यकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका प्रयोजन केवल यही हो सकता है कि सरकार अमरीकी के लिये पी० एल०-480 के अन्तर्गत जमा हुई बहुत बड़ी राशि को खर्च करने का कोई रास्ता निकालना चाहती है। सरकार ने इस योजना को स्वीकार करके बड़ी भारी भूल की है क्योंकि इस शिक्षा प्रतिष्ठान का हमारे सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने हाल के कई भाषणों में कहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही है जो औद्योगिक नीति संकल्प के विरूद्ध हो। औद्योगिक नीति संकल्प में एकाधिकारों तथा आर्थिक शक्ति को कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में जाने से रोकने की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट घोषणा की गई थी। परन्तु हो क्या रहा है? एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार 75 बड़े समूहों की जिनका 1536 कम्पनियों पर नियंत्रण है, कुल आस्तियां 2606 करोड़ रुपये हैं जो गैर-सरकारी निगम क्षत्र की कुल आस्तियों का 46.9 प्रतिशत है। इन 75 समूहों की कुल प्रदत्त पूंजी 646.32 करोड़ रुपये है जोकि इस देश की कुल मिला कर लगभग 25000 कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी का 44.1 प्रतिशत है। यह औद्योगिक निति संकल्प में उल्लिखित उद्दश्यों से कैसे मेल खाता है।

प्रति वेदन में इसके पांच कारण बताए गये हैं। (1) बड़े पूंजीपति पूंजी आसानी से जुटा सकते हैं और लाइसेंस भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं हालांकि हम सब को पता है कि इनमें से बहुत से लाइसस प्रयोग में नहीं लाए जाते है। (2) लाइसेंस देने वाले अधिकारी तथा लाइसेंस प्रणाली ऐसी है जिससे बड़े समूहों का पक्ष मजबूत होता है और छोटे पूंजीपतियों के बड़ी परियोजनाएं हाथ म लने के रास्ते में रूकावट उत्पन्न होती है। (3) बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं भी बड़े पूंजीपतियों को ही अधिक फायदा पहुंचाती हैं। (4) आयात प्रतिबन्ध तथा विदशी मुद्रा ने भी संरक्षित बाजार उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है।(5) विदेशी सहयोगकर्ता भी बड़े समूहों को ही तरजीह देते हैं।

मेरा यह सब कहने का अभिप्राय यह है कि एकाधिकार में यह वृद्धि देश में एक निर्णायक तत्व है। वे आज न केवल राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग चट कर जाते हैं अपितु इससे हमारे देश में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी को भी प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि विदेशी सहयोगकर्ता बड़े पूंजीपतियों के साथ ही सहयोग करना चाहते हैं। यदि कृषि क्षेत्र की भी कोई एसी जांच कराई जाये तो वहां पर भी जमाव करने की इस प्रवृत्ति का पता लगेगा। यह एक तथ्य है कि बाजार में आने वाले अनाज की मात्रा लगातार घटती जा रही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनाज अधिक मात्रा में जमा किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनाज का उत्पादन में प्रतिवर्ष औसतन 3 से 4 प्रतिशत वृद्धि हो रही है और जन संख्या में 2 से 2½ प्रतिशत वृद्धि हो रही है। फिर भी अनाज की इतनी अधिक कमी क्यों है? सचाई यह है कि थोक व्यापार पर बड़े व्यापारियों के बढ़ते हुए नियंत्रण के कारण बाजार में माल कम आ रहा है। इसलिय यह तथा कथित कमी बनावटी है और स्वयं मनुष्य की बनाई हुई है। इसके केवल दो ही उपाय है: या तो सरकार पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज आयात करे या जमाखोरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करे। इन निहित स्वार्थ वाल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार राजनैतिक तथा अन्य किन्ही कारणों से कार्यवाही नहीं करना चाहती है। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना है अर्थात् पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात। यह एक बहुत ही खतरनाक रास्ता है जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा इलक्ट्रोनिक कम्प्यूटर लगाये जाने से हजारों कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

बड़ी चतुराई से बोनस शेयरों पर से कर हटा दिया गया है इसका प्रभाव यह होगा कि कर्मचारियों को बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले बोनस के लिये जो फालतू धन निर्धारित किया जाता था उसमें बहुत कमी हो जायेगी।

उर्वरकों के बारे में इन अमरीकी भागीदारों को दी गई रियायतों के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कल को वे कहत ह कि उन उवरक कारखानों में भारत सरकार के श्रम कानूनों से काम नहीं चल सकता और वहां पर अमरीकी श्रम कानून लागू किये जाने चाहिये,

तो क्या सरकार उनकी इस मांग को टाल सकती है? यह सरकार अवश्य ही उनकी आज्ञा का पालन करेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जानबूझ कर मजदूरों को भेड़ियों के सामने फेंक रहा है जिससे सारे देश में श्रमिक अशांति फैल सकती है।

प्रधान मंत्री ने अपने रेडिओ भाषण में कहा है कि इस वर्ष की योजना के दो मुख्य पहलू हैं एक तो कृषि क्रांति की बुनियाद रखना और दूसरा बुद्धिमत्ता से आयात प्रतिबन्धों को कम करना तथा अनावश्यक नियंत्रणों को हटाना है। ये दोनों ही विश्व बैंक की मांगें है। हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है परन्तु इस मिश्रण के अनुपात के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। राष्ट्रीयकरण कोई सिद्धांत नहीं है परन्तु सरकारी क्षेत्र के विकास के बारे में राष्ट्रीयकरण की भी कल्पना की गई थी। 1955 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करके इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। ग्यारह वर्ष व्यतीत हो गये हैं परन्तु किसी एक-आध सार्थ को छोड़ कर इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। ऐसा लगता है कि व्यावहारिक रूप में राष्ट्रीयकरण की नीति को त्याग दिया गया है। इसलिये हमें बताया जाना चाहिये कि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस किस का कितना हाथ होगा।

इस वित्त विधेयक में दिये गये कर प्रस्तावों से उन्हीं गिने चुने लोगों को ही फायदा पहुंचेगा जो राष्ट्र की अधिकांश आय के स्वामी बन गये हैं। ये कर प्रस्ताव हमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर नहीं ले जा रहे हैं जिनके लिये यह सरकार तथा यह सभा वचनबद्ध है।

इसके बाद काले धन का प्रश्न आता है। हमारे सामने धन जुटाने की बिकट समस्या है। लोग इन प्रस्ताओं को तबतक नहीं स्वीकार करेंगे जब तक कि उन्हें इस बात का यकीन न हो जाये कि इस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, देश में करोड़ों रुपये का काला धन है। काले धन की समस्या को सुलझाने तथा उसे बाहर निकलवाने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हरिदास मुंदड़ा के पास विदेशों में 10 लाख पौंड हैं यह सब काला धन बेनामी सौदों की कमाई है। सभा को बताया जाना चाहिये कि सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है। यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो फिर लोग उत्पादन शुल्कों तथा अप्रत्यक्ष करों का अधिकाधिक बोझ क्यों सहन करें।

देश में आज संसाधनों का जो संकट बना हुआ है, वह अनावृष्टि आदि जैसे दैविक कोप के कारण नहीं अपितु सरकार के कारनामों के फलस्वरूप है। सरकार को यह बताने चाहिये कि इन परिस्थितियों में, जबकि हमें अति गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, उसका क्या करने का विचार है।

श्री रामनाथन चेट्टियार (करूर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश पिछले वर्ष से बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के हाल के संघर्ष के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले बहादुर जवानों तथा अधिकारियों को मैं उनकी शूरता, साहस तथा कर्तव्य निष्ठा के लिये उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

देश के विभिन्न भागों में सूखा पड़ा हुआ है और खाद्यान्नों की कमी है। विरोधी दल वाले राष्ट्रीय कर्तव्यों तथा देश भक्ति की भावनाओं की अवहेलना करते हुये अभाव तथा कमी की स्थिति का लाभ उठाकर 'बन्द' संगठित कर रहे हैं और वे स्थिति को और भी गंभीर बना कर ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिनमें सरकार काम न कर सके। किन्तु देश के लोग कुछ सदस्यों से जो आज विरोधी दलों में हैं कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। वे विरोधी दलों के कहने पर झुकने वाले नहीं है। विरोधी दलों की इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण देश के कुछ भागों में हिंसात्मक कार्यवाहियां भी हुई हैं।

2—67 Lok Sabha/66

[श्री रामनाथन चेट्टियार]

आर्थिक सर्वेक्षण हमारे आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिम्बित करता है। कृषि उत्पादन को बढाने के लिये हमें सभी संभव प्रयत्न करने चाहिये। किसानों को अच्छे बीज तथा उवरक देकर हम प्रति एकड़ उपज बढ़ानी चाहिये। वित्त मंत्री को उवरकों के आयात के लिय पर्याप्त विदेशी मुद्रा देने में हिचकना नहीं चाहिये जब तक कि देश में उर्वरक कारखाने स्थापित नहीं हो जाते। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। भारत एक बिशाल देश है। हमारे लिय आत्मनिर्भर बनना कठीन नहीं है आवश्यकता केवल संकल्प-शक्ति की है। भूमि के उचित प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

औद्योगिक उत्पादन के मामले में कोई सराहनीय परिणाम नहीं निकले हैं। हड़ताल आज एक आम चीज हो गई है। श्रम क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को देशभक्ति की अधिक भावना रखनी चाहिये और उन्हें राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुये हड़तालों आदि को रोकना चाहिये ताकि उत्पादन पर प्रभाव न पड़े। केवल एसा किये जाने पर ही औद्योगिक क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जा सकता है।

आज करों के भारी बोझ के कारण लोगों की क्रय क्षमता कम हो गई है। प्रति दिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं यथा चीनी, कपड़ा, तम्बाकू आदि पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने कारण उनकी कीमतें चढ़ गई ह। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल चीनी की ही कमी नहीं अपितु क्रय-शक्ति की भी कमी है। इसी कारण वे लोग वर्तमान दरों पर चीनी नहीं खरीद सकते।

मिट्टी के तेल की कमी के कारण ग्रामीण क्षत्रों के लोगों को विशेष रूप से कठिनाई हो रही है। मिट्टी के तेल की कमी के लिये तेल कम्पनियां उतनी ही जिम्मेदार ह जितने कि व्यापारी लोग। तेल कम्पनियों क सहयोग के बिना व्यापारी इस कृत्रिम कमी को पैदा नहीं कर सकते। मिट्टी के तेल की केवल अच्छी किस्म पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया है किन्तु लोगों को घटिया किस्म के मिट्टी के तेल के लिये भी बढ़ी हुई कीमत ही देनी पड़ती है। वित्त मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि कम से कम अगले वर्ष मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क इतना कम कर दिया जाय कि लोग दैनिक जीवन की यह अत्यावश्यक वस्तु खरीद सकें।

इस समय निजी आय पर कर इतना अधिक है कि करदाताओं के लिये कोई बचत करना संभव नहीं है। वित्त मंत्री को निगम कर तथा निजी कर दोनों के ढांचे को इस प्रकार यक्ति-युक्त करना चाहिये जिससे न केवल पूंजी लगाने की संभावनाओं को बढ़ावा मिले बल्कि लोग यथासंभव अधिक बचत करने के योग्य भी हो सकें। जहां तक देश में बैंकों का सम्बन्ध है, मैं 17 वर्ष से अधिक समय तक रिजर्व बैंक का एक निदेशक रहने की हैसियत तथा व्यवहारिक अनुभव के आधार पर यह बात कहने का दावा करता हूं कि देश में बैंक व्यवसाय ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा रहा है। बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 देश में बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिय पर्याप्त नहीं है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि वर्तमान भारत का रिजर्व बैंक अधिनियम देश के बैंको पर नियंत्रण रखने के लिये पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है। बैंको के इनचाज इस अधिनियम की त्रुटियों का लाभ उठाकर न केवल अभ्यांशधारियों को ही अपितु उन बैंकों में धन जमा रकने वाले लोगों को भी हानि पहुंचा सकते हैं।

वित्त मंत्री महोदय को देश में सहकारी बैंकों, अनुसूचित बैंकों तथा एक्सचेंज बैंकों के समूचे ढांचे की जांच करने क लिय केन्द्रीय बक जांच आयोग नियुक्त करना चाहिये। सहकारी बैंकिंग संस्थाओं की जांच किय जाने का काम इसी आयोग को सौंपा जाना चाहिये।

मद्रास राज्य के त्रिचनापल्ली जिले में नोथल नदी योजना काफी समय से विचाराधीन है। इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिये। इसी जिले के कुलीतलाई तालुक में कोटगनार नदी योजना को भी चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिये ताकि इस क्षत्र में अधिक भूमि की सिंचाई हो सके।

सेतसमद्रम योजना की एक राष्ट्रीय माना जाना चाहिय। इस योजना को क्रियान्वित कियें जाने पर जहाजों को श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़गा और इससे भाडे तथा पत्तन शुल्क के रूप मे कोलम्बो म होने वाला व्यय भी बच जायेगा। सलिये इसे चौथी पंचवर्षीय योजना म शामिल किया जाना चाहिये।

Shri Sumat Prasad (Muzaffarnagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the experience we gained from the Pakistani aggression is, we cannot defend our borders with the assistance of other countries. During our conflict with Pakistan the U.S.A. & the U.K. had withheld not only the military aid but also the promised economic aid for the Third Five Year Plan.

The formulation of our fourth Five Year Plan is dependent upon aid commitments from the World Bank. It is dangerous to depend upon foreign aid for inplementation of our plans of course marginal assistance can be obtained. But economic independence is essential to preserve democracy. Time has come when we should consider what change is called for in our policy of planning.

There is a lot of talk in this House about the high level taxation on the corporate sector. The Corporate Sector is well established and organised, they have resorces and they control the press. Moreover, they have had an easy approach to the Government. But the condition of the people in rural areas has not improved during the three plans. If the existing state of affairs continues, there will be a revolution in the country.

The existing system of our education does not provide avenues of employment. Educated people cannot stand on their own legs. No change has been made in our educational system with a view to check growing unemployment. In order to check unemployment in the rural sector, Village and small scale industries should be set up in rural areas. Efforts should be made to make these areas prosperous and also create avenues of employment there. This will check migration of rural population to urban areas.

Market arrivals of foodgrains will not improve the situation unless remunerative price is given to the agriculturist for his produce and means to increase production are provided to him.

The condition of agricultural labour and petty farmers has deteriorated in spite of our plans. The condition of an ordinary labourer has not improved much in the urban areas. They are being crushed under the burden of heavy taxation. Such a state of affairs may lead to dangerous developments.

Steps should be taken to unearth black money. This money is responsible for increase in prices. The poor section of society suffers from this account. A solution should be found to these problems which are inter-related.

Although adequate stocks have been sent to scarcity areas in Orissa, the starvation deaths might take place there due to the fact that people are not in a position to purchase foodgrains at the market price.

Discussion on controlling and regulation is also held in this House. Although introduction of controlling system is necessary for equitable and proper distribution in the scarcity areas, but it requires an honest distribution machinery, in absence of which blackmarketing raises its ugly head and prices increase. Scarcity conditions create inflation and these two are inter-related. Serious thought will have to be given to find out ways of controlling inflation

[Shri Sumat Prasad]

The appointment of Administrative Reforms Commission is welcome. It appears the report of this Commission will render twenty to twentyfive per cent Government employees surplus both in Centre and the States. A pool of such employees could be formed for utilization of their services in the implementation of the Fourth Five Year Plan.

The performance of the public sector is not upto the mark. Public sector is meant to give relief to the people. Technical personnel, who know the job should be employed in the public sector undertakings, not the I.A.S. people, who know nothing about it, unless that is done, public sector will always be a target of criticism and will also lead frustration among people. An all-out efforts should be made to make public Sector a success. The public sector and the private sector have to work in collaboration to make the people happy and bring in prosperity in society.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज व्यापक चुनौतियों के कारण हमारी संस्कृति तथा समाज में 'अभय' के मूलभूत सिद्धान्त तथा महत्व को खतरा पैदा हो गया है। भय तथा हिंसा ने हमारे प्रजातंत्र और हमारे समाज के अन्तःकरण को पिछले कुछ समय से कुरेदना आरम्भ कर दिया है। आज हमारे समाज के क्षितिज विभिन्न प्रकार के भयों से ढके पड़े हैं। इन भयों का उन्मूलन करना जरुरी है।

इस संदर्भ में बस्तर में जो कुछ हुआ है, उससे सभा अवगत है। वहां हुई घटना की जांच करने के लिये तत्काल आयोग की नियुक्ति भी की गई है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या घटना की निष्पक्ष जांच हो सकेगी। ऐसा मालूम होता है कि आज बस्तर में पूरी तथा निष्पक्ष जांच के लिये आवश्यक परिस्थितियां नहीं हैं। मालूम हुआ है कि बस्तर जिले में सशस्त्र एस०ए०एफ० गश्तीदल भारी संख्या में है। वे बस्तर के लोगों को आतंकित कर रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। वे लोगों से सब प्रकार की घूस ले रहे हैं और किसी प्रकार का साक्ष्य देने के लिये जगदलपुर नगर में न जाने के लिये बाध्य कर रहे है। वे लोगों से यह भी कहते हैं कि वे राजमहल में गोली कांड के बारे में किसी प्रकार की जानकारी न दे और यह कह दें कि इस घटना से हमारा कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

जीन अफसरों के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, व अभी तक बस्तर में जिम्मेदार पदों पर लगे हुय हैं, उनकी उपस्थिति से ही वहां आतंक का शासन जारी है। सारे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। जो कोई भी उस क्षेत्र का दौरा करता है पुलिस उसका पीछा करती है।

यह बहुत ही खेद की बात है कि बस्तर जांच सहायता समिति के आयोजक के रुप में मैने विभिन्न वकीलों को जो तार भेजे थे वे पांच-छः दिन के बाद उन्हें मिले हैं और ये तार लिफाफों के अन्दर नहीं दिये गये हैं।

एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के श्री प्रेम दास के एक वक्तव्य के अनुसार सारे बस्तर में पुलिस राज्य है। जब तक सशस्त्र पुलिस वहां से नहीं हटाई जायेगी, जांच आयोग को तथ्यों की जानकारी नहीं हो सकती। राज्य सभा के सदस्य डा० खूबचन्द बघेल ने कहा है कि वहां के गांवों में पुलिस के अत्याचार तथा आतंक के कारण जीवन सामान्य नहीं है। लोग भयभीत हैं।

ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री को बस्तर का दौरा करना चाहिये। जांच ठीक तथा निष्पक्ष रुप से किये जाने के लिये ठीक परिस्थितियों का पैदा किया जाना आवश्यक है। धारा 144 हटा ली जानी चाहिय और एस०ए०एफ० गश्ती दल, जिसके प्रति लोगों की घोर घृणा है और जो लोगों को आतंकित करता है, वहां से हटा दिया जाना चाहिये और उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिये।

'बस्तर की कहानी' तथा 'लौह पुरुष पंडित द्वारकानाथ प्रसाद मिश्र की कहानी" जैसी पुस्तकें समूचे बस्तर जिले में भारी संख्या में बांटी जा रही है ताकि लोगों को भ्रम में डाला जा सके, लोक-मत को दूषित किया जा सके और एसी स्थिति उत्पन्न की जाय जिसमें जांच निष्पक्ष, उचित रूप से तथा पूरी तरह वास्तविक तथ्यों के साथ न हो सके।

आवश्यकता इस बात की है कि सरकार प्रजातंत्रीय आदेशों तथा सिद्धान्तों का जबानी बखान न करे के उनका वास्तविक रूप में पालन करें जहा तक आपात कालीन स्थिति को बनाये रखने का सम्बन्ध है, संविधान के अन्तगत आपातकाल की उद्घोषणा भारत के किसी भाग तक सीमित रखी जा सकती है। अनुच्छेद 352 तथा 357 के अन्तर्गत समूचे देश तथा देश के किन्हीं विशिष्ट भागों के लिये आपात काल की घोषणा की जा सकती है। सरकार ने जिस रुप में और जिस प्रकार इसे वापस लेना चाहा है, वह सराहनीय नहीं है, तथापि गृह-कार्य मंत्री के इस आश्वासन का कि आपातकाल केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जायेगा, स्वागत है।

मै तो यह समझता हूं कि श्री नन्दा का अपराध नहीं है बल्कि अपराध इस बात का है कि उन्होंने गलत संवधानिक परामर्श लिया। मैं आशा करता हूं कि मौलिक अधिकारों के बारे में जो न्यायालयों के अधिकार लिये हैं, वह समाप्त होंगे।

मै सदन का ध्यान इस बात की ओर भी खींचना चाहता हूं कि चीन शीघ्र ही एक उद्जन बम छोड़नेवाला है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस धमकी का उत्तर किस प्रकार देगी क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इस देश का सौभाग्य है कि हमारे वित्त मंत्री एक यथार्थवादी व्यक्ति हैं।

अपनी विदशी मुद्रा संबंधी कठिनाई के बारे में सरकार की नीतियों का खंडन योजना आयोग के सदस्य श्री बरवे ने ही किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि विदेशी मुद्रा का बजट बहुत घटिया तरीके से बनाया है और वह बहुत असंतोषजनक है। म मंत्री महोदय से इसका भी उत्तर चाहता हूं।

बस्तर जिले में इस समय ऐसा वातावरण नहीं है कि वहा निष्पक्ष जांच हो सके।

Shri Lakhmu Bhavani (Bastar) : I represent the Bastar district in Parliament. After the firing I was there thrice but I always found section 144 of Cr. P.C. in force. If Section 144 is removed, I can go there and place before Parliament the correct number of persons killed in firing.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : The difference between our import and export is to the tune of Rs. 400 to Rs. 500 crores. This is all paid in foreign exchange.

How has Japan progressed so much ? They do not import a machine twice. After once importing a foreign machine, they manufacture it in their own country. But we go on importing one type of machine again and again. In freight charges also the Indian shipping gets only 11% and the foreign shipping Companies get 80% of the freight charges.

Again according to Merchant Shipping Act, 1929, coastal trade has to be done entirely by the Indian ships. But this too is not being adhered to. I want to know the reason for the foreign tankers to do coastal trade. Even Government's own cargo is handled by the foreign ships. In this way we give Rs. 140 crores per year to the foreign shipping companies by freight charges.

From 1921 to 1965 an investment of Rs. 147 crores has been made. We pay to foreign companies Rs. 140 crores annually. If we make our own ships, we can save this drain of huge amount. In our Vishakhapatnam factory we manufacture 10,000 tons of ships whereas the world is manufacturing about 3 crores tons of ships. We have got so many steel plants and yet we cannot manufacture ships.

[Shri Raghunath Singh]

For repair of ships we have to sent them to Singapore, Aden, U.K. and Tokyo as we do not have even a single dry dock. With an investment of Rs. 3 crores we can have a yard and a dry-dock of our own and repair our ships here itself.

Indian tankers should be used for coastal trade.

The shipping material which is imported in U.K. Japan and Sweden, no import duty is charged. Japan even does not charge any income tax on the capital invested in shipping industry. Germany too does not charge any income tax on such ventures.

I want to inform that shipping is your second line of defence during the war time. All your ships are the ports of your frontier. Do not treat it like an industry.

If you do not get engines in India, make import of engines duty free. If you want advancement in shipping industry, you will have to give it higher priority as shipping is your second line of defence.

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में वित्तीय नीतियों में सुधार की बात कही है। उद्देश्यों में तो हम ठीक थे परन्तु कार्य करने में इतने नहीं।

मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ प्रस्तुत कर सकता हूं जिसके कारण हमारे देश को विकास के मामले सिवाय इन्डोनेशिया के बाकी सब से नीचे रखा है। जापान ने 10 प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि की। ताईवान में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लंका में 3.7 प्रतिशत तथा पाकिस्तान में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और भारत में केवल 3.3 प्रतिशत की। इन्डोनेशिया में यह वृद्धि 2.8 प्रतिशत की हुई।

जहां तक मूल्यों के बढ़ने का संबध है, हमारे देश में शायद सब से अधिक बढ़े हैं। 1950 में मल्यों का इन्डेक्स 95 था और 1964 में यह 134 हो गया। अमरीका में यह 107 है और फ्रांस में 108 है तथा पश्चिमी जर्मनी में 114 है। इस से सिद्ध होता है कि उन देशों में वास्तविक आय बहुत बढ़ गई हैं।

इस संदर्भ में मैं आपको स्पेन का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां 1959 तक स्थिति बड़ी खराब थी। परन्तु उस वर्ष वहां एक योग्य व्यक्ति श्री अल्बर्टो उल्लाग्रेटेक्स को वित्त मंत्री बना दिया। आज वहां यह स्थिति है कि 7 आटोमोबाइल कारखाने हैं जिनमें 1,75,000 आटोमोबाइल प्रतिवर्ष बनते हैं। सकड़ों और कारखाने खुल गय ह। इस से यह सिद्ध होता है कि एक योग्य व्यक्ति ने कितना बड़ा कार्य कर दिखाया।

हमे भी उसी दिशा में सोचना चाहियें। जब तक हम बढ़ती कीमतों पर काबू नहीं करेंगे हमारा विकास बहुत धीमा होगा।

श्री नि० चं० चटर्जी (बरद्वान) : जब श्री शचीन्द्र चौधरी वित्त मंत्री बने तो मैं शायद पहला व्यक्ति था जो उन्हें बधाई देने गया और मैंने उन से यह आशा की कि वह श्री मुरारजी देसाई की भान्ति जिद्दी और रुखा नहीं होंगी।

मैं ने सोचा था कि वह राष्ट्र की पुकार सुनेंगे और सोना नियन्त्रण अधिनियम को समाप्त कर देंगे। श्री हनुमन्तैय्या ने भी इस अधिनियम का विरोध करके सदन के अधिकांश सदस्यों का विचार प्रकट किया। इस अधिनियम को तीन सिद्धान्तों के लिये रखा था परन्तु यह तीनों में असफल रहा है।

इसका पहला सिद्धान्त तो मूल्यों को कम करना था परन्तु यह उसमें विफल रहा।

दूसरे उन्हों ने सोचा था कि सोने में तस्करी समाप्त हो जायेगी परन्तु वह भी न रुक सकी।

तीसरी बात यह थी कि लोगों की सोना रखने की आदत समाप्त हो जायेगी परन्तु वह तो सोने के लिये अब भी पहले की भांति लालाचित हैं।

इन बातों के कारण मैं श्री हनुमन्तैय्या की मांग का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस विधयक को समाप्त करे।

मैं अपने मित्र डा० सिंघवी का बस्तर में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने के बारे में मांग का समर्थन करता हूं। आज ही मैं जगदलपुर की बार संस्था के अध्यक्ष से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि वहां कार्यपालिका और न्यायपालिका अब भी एक ह। लोगों को डराया जाता है। जो पकड़े गये हैं उनकी जमानत पर रिहाई तब होती है जब वह लिखकर यह देते ह कि उनका अपराध था। जब ऐसी बात हो तो फिर न्याय की क्या आशा? आचाय कृपलानी ने इस मामले में जो रुचि ली है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।

आज देश में मजदूर संतुष्ट नहीं है। अब नई मशीन आ रही है जिसका नाम "कम्प्यूटर" है जोकि एक मशीन 14,000 व्यक्तियों का कार्य करेगी। उन व्यक्तियों का फिर क्या बनेगा?

1963 में यह विनिश्चय किया गया था कि एक कम्प्यटर लगाया जाए। एक कम्प्यूटर का 5 लाख रुपय प्रति मास किराया है। उसी वर्ष 2,819 लोगों को रखा गया था क्योंकि पालिसियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। 9.25 लाख पालिसियां बढ़ी थीं। अगले वर्ष जबकि उतनी ही पालिसियां बढ़ी थी परन्तु केवल 912 लोग और रखे गये। प्रति वर्ष 2,000 अथबा 3,000 नये कर्मचारी रखे जाते थे परन्तु कम्प्यूटर के आने पर भर्ती वार्षिक भर्ती का 30 प्रतिशत ही रह गई।

इस बारे में सरकार को अपनी नीति की घोषणा करनी चाहिये। सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि क्या कलकत्ता में दूसरा कम्प्यटर लगाया जाएगा। यदि हां, तो गरीब लोगों के रोज़गार के लिये उस से क्या खतरा है? कितने हज़ार लोग बकार हो जायग? मेरी जानकारी यह है कि 14,000 लोगों पर उसका असर पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भतपूर्व वित्त मंत्री की नीति पर चलेगी और छंटनी नहीं करेगी या अपनी नई नीति लागू करेगी। यदि सरकार छंटनी करेगी तो कितने हज़ार लोगों को निकाला जाएगा? क्या इन गरीब लोगों को कहीं और रोज़गार दिया जाएगा?

Shri Parashar (Shivpuri) : I congratulate the Finance Minister for presenting a balanced budget in such a difficult situation when, internally, the country is facing numerous economic problems and externally the threat to our borders still continues.

There are two or three wrongs in our country for the rectification of which a high-power commission should be appointed. Government should pay proper attention to the matters and if the present policies in connection with them are corrected, our total revenues would go up.

Sometime back reference was made to the problem of black money. Government had sitelf indicated from time to time that the hidden money in the country was estimated about Rs. 3,000 crores. Government seems to be lacking in boldness. If bold steps are taken that money could be unearthed. Government has sufficient powers to deal with the matter in a firm manner but I think well to do so also appears to be lacking. If Government takes some radical steps, the menace of black money could be put an end to within three months. A high power Commission should be set up which should examine the problem and devise methods to solve it.

[Shri Parashar]

Similarly, huge arrears of income tax and other taxes are lying unrealised. Much paper work has been done but nothing has been realised from the evaders. Government should appoint a high-power Commission which should examine this problem also and recommend remedies. In this way, crores of rupees could be realised.

Besides, there are a number of white elephant organisations or institutions. A lot of money by way of grants or loans is being given to these organisations which are frittering away public money. Government should stop giving grants or loans to such organisations.

Government has declared state of emergency in the country. It is a pity that we are begging for foreign aid and when we could increase our resources within the country itself. The Planning Ministers visit to the U.S.A. and request for help has done no credit to our country.

We might have two sets of plan—one based on our own resources and the other based on foreign aid. If foreign aid is not forthcoming on honourable firms, the aid-based plans should not be implemented.

Madhya Pradesh has not received a just treatment at the hands of the Government. Madhya Pradesh had always been producing ample foodgrains. Every year foodgrains used to be sent out to other parts of the Country. Due to natural calamities, that state is facing famine conditions now. In these circumstances, the Government of Madhya Pradesh and the Apex Bank requested the Reserve Bank of India to give some loan from the credit stabilisation Fund but the Reserve Bank, instead of granting any loans, assumed a very unwholesome attitude. Why this step-motherly treatment is being meted out to Madhya Pradesh ?

Reserve Bank has also done certain wrong, it has been partial in giving concessions etc. If I expose all these things, its reputation will suffer. On our own hand Government asks the agriculturists to augment production but does not give [any financial help to them when they stand in need of such help due to famine. Where else should they go for help ?

The Reserve Bank has not been fair to Madhya Pradesh. What is the use of a Reserve Bank when my State's request for help from its credit stabilisation Fund to enable the co-operative Societies to meet the credit needs of the farmers cannot be met?

Government charges levy in my State and Co-operative Societies have been authorised to realise the money. The agriculturist have been told that they would be paid the actual price. Besides, after sale, 50 per cent of the profit, if any, shall also be paid to them. This is a nice scheme, but actually due to paucity of funds, the co-operative societies are not able to make payments to the peasants. Government should properly manage this scheme. The agriculturist has to face a lot of trouble for not a single grain can be purchased privately and the co-operative society does not have any money. The Reserve Bank does not give anything and if Central Government is approached, it directs them to go to the Reserve Bank. All these matters should be minutely looked into.

In the Gwalior-Guna region of Madhya Pradesh, there are rich iron deposits in a 150 miles long and 150 miles wide region. Government has not taken any action in spite of request that prospecting should be undertaken in that area. When this matter was taken up in the consultative committee and other committees, it was told that no funds were available.

It was in 1962 that I had raised the matter concerning water supply in my region. Women with child in lap have to bring water in pots on their heads from a distance of about 8 miles in the summer season. I have been raising this matter in every consultative Committee. Now in 1966, I am told that scheme is under preparation.

Government has not been able to remedy the menace of decoits in the Chambal valley. In order to remedy this problem , a military school should be opened in that area so that youth may receive training there.

From the point of view of foresight I have all along been stressing the necessity of connecting Kanpur, Jhansi and Babina Cantonments by railway. In times of emergency movement of forces will be much facilitated in that way.

The bridge proposed to be built near Pali(Sawai Madhopur) should be completed soon. The proposal should not end on files only; I hope the work will be taken up shortly and completed within a short period.

Government should go in for manufacture of atom bombs in the interest of national security.

The country is facing a number of problems today. These problems cannot be solved until Government implements in policies fearlessly and boldly. Firm policies based on force should replace diplomacy. Then the country can march towards greatness.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे माननीय मित्र, वित्त मंत्री बड़े चतुर वकील हैं । उन्हें करों से सम्बन्धित नियमों तथा वित्तीय नियमों का काफ़ी अनुभव है । वह यथार्थवादी है और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वह उत्पादन-प्रधान बजट पेश कर रहे हैं । चूंकि उत्पादन पर वह मुख्य ध्यान दे रहे हैं, वह गैर सरकारी क्षत्र का विश्वास बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं । इस के लिए मैं उनको दोषी नहीं ठहराता । ऐसी स्थिति एक दिन में ही नहीं हो गई है । यह तो उन नीतियों का परिणाम है जिन पर हम वर्षों से चलते आ रहे हैं । समाजवाद के पर्दे में पिछले पन्द्रह वर्षों में जो योजनाएं बनाई गई हैं वास्तव में उनके अन्तर्गत हमारी अर्थ-व्यवस्था का किसी दूसरे तरीके से निर्माण हुआ है । और हम अधिक से अधिक ग़ैर-सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी सहायता पर निर्भर करने लगे हैं । ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का दबाव काफ़ी सफ़ल रहा है और भविष्य में और भी सफ़ल होगा क्योंकि सरकार ने लोकहित की कोई चिन्ता नहीं की है बल्कि देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों का अधिक ध्यान रखा है । अत: इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं है हालांकि वित्त मंत्री ने अपने "इकानामिक सर्वे" में अर्थ-व्यवस्था की बुरी हालत बतलाई है और यह चेतावनी दी है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय बढ़ जाएगा परन्तु वित्त विधयक में अपने प्रस्तावों में इन चुनौतियों को कोई स्थान नहीं दिया है । इसके विपरित उन्होंने निगमित क्षेत्र तथा उद्योगपतियों को इस आशा से काफ़ी सहायता दी है कि इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होगी ।

वित्त मंत्री ने इस के अतिरिक्त यह भी कहा था कि सरकारी व्यय में कटौती किया जाना बहुत आवश्यक है । किन्तु कटौती केवल ग़ैर-विकसीय व्यय में ही नहीं की गई है बल्कि योजना सम्बन्धी तथा विकास सम्बन्धी व्यय में भी की गई है ।

पिछले पन्द्रह वर्षों में, प्रथम बार, चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय में 266 करोड़ रुपये की कमी हुई है । योजना पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का 144 करोड़ रुपये कम व्यय होगा । राजस्व व्यय में जो उत्पादन से भिन्न है, 220 करोड़ की वृद्धि हो जायगी । केवल चालू वर्ष में योजना व्यय तुलना में 36 करोड़ रुपये कम रहेगा । प्रतिरक्षा पर व्यय 3 प्रतिशत कम हो जाएगा ।

प्रशासन सम्बन्धी व्यय में करीब 29 करोड़ रुपय की वृद्धि हो जायगी । जब पूंजीगत व्यय और योजना व्यय में कमी हो गई है तो इसके फलस्वरुप योजना के लिये विराम का समय आ गया है । यह इस लिए हुआ है कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र ऐसे विराम की मांग कर रहा था । अत: हम नहीं कह सकते कि

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारुप क्या होगा। चौथी योजना का काल 1 अप्रैल से आरम्भ हो गया है फिर भी योजना आयोग से कोई नियमित प्रारुप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अत: प्रगति की बजाय हम विराम करे हुए हैं और प्रगति के लिये हम ग़ैर-सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी सहायता पर पूणतया निर्भर हैं।

[श्री पें० वेंकटासुब्बय्या पीठासीन हुए
SHRI P. VENKATASUBBAIAH *in the Chair*]

हमारे योजना मंत्री ने जो अमरीका में हैं, एक पत्रकार सम्मेलन में स्पष्ट कहा है कि इस समय भारत की स्थिति बिलकुल वैसी ही है जैसी कि एक पर्वतारोहण करने वाले व्यक्ति की शिखर के निकट पहुंचने पर होती है जबकि वह बाहरी सहायता के बिना गिर जायगा। वर्षों की योजनाओं के बावजूद आज हमारी यह स्थिति है।

सरकार द्वारा व्यय-कर को उठाये जाने की कोई तर्कसंगति नहीं है। इसके अतिरिक्त, जब हमें इस समय रुपये की इतनी आवश्यकता है तो सरकार ने पुण्यार्थ न्यासों को कर-मुक्त क्यों किया गया हैं। ये न्यास उद्योगों में रुपया लगा कर लाभ कमाते हैं।

अत: वास्तव में वित्त मंत्री ने कर व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया है। यदि कुछ किया है तो वह सम्पन्न वर्ग के हित के ही लिये किया है। गरीब वर्ग के सुधार के लिये उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं रखा है और मूल्यों को कम करने अथवा स्थिर रखने के लिये कोई योजना नही बनाई है। वित्त मंत्री ने चिन्ता तो प्रकट की है परन्तु प्रस्तावित वित्तीय उपायों से तो मुद्रा-स्फीति बजाय कम होने के और बढ़ेगी। आज मूल्यों की हालत चिन्ताजनक है। तीसरी योजना के दौरान थोक मूल्यों में 32 प्रतिशत वृद्धि हुई। खाद्यान्न के मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। सब वस्तुओं के लिये 1952–53 में औसत देशनांक 100 रखते हुये, 1955–56 में 92.3 से 1960–61 में जो दूसरी योजना का अन्तिम वर्ष था 124.8 हो गया था। 1965–66 में जो तीसरी योजना का अन्तिम वर्ष है वह 165 हो गया। मार्च 1965 में मूल्य देशनांक 151.5 था और मार्च 1966 में 172.3 हो गया है।

अत: मूल्यों में स्थिरता की बजाय उनमें वृद्धि होती रही है। मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये अधिक प्रत्यक्ष करों का लगाया जाना और अधिक लघु बचत अथवा अधिक उधार लेना अच्छे उपाय हो सकते थे। परन्तु इस सम्बन्ध में भी वित्त मंत्री ने समाज के धनवान वर्गों को ही अधिक ध्यान में रखा है। प्रत्यक्ष करों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी आशा की जाती थी। अप्रत्यक्ष करों में 52.86 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मुद्रास्फ़ीति को रोकने के लिये खुले बाज़ार से ऋण एक और उपाय है परन्तु यह चालू वर्ष में 331 करोड़ रुपये था और अब कम होकर 280 करोड़ हो गया है। अप्रत्यक्ष करों से केवल मूल्य ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि समाज में असमानता की खाई और चौड़ी होगी और धनी वर्ग के पास अधिक रुपया रहेगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि काले धन को प्राप्त करने के लिये किये गये उपायों का क्या परिणाम निकला है। 6 जनवरी को वित्त मंत्री के कार्यभार संभालने के पश्चात केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने अपने अफ़सरों को एक परिपत्र जारी किया था कि भविष्य में और छापे तब तक न मारे जाय जब तक उन्हें इस सम्बन्ध में अग्रेतर आदेश न दिये जायें। कलकत्ता में सीमाशुल्क तथा विदेशी मुद्रा अनुभाग ने दो पार्टियों को नोटिस दिये हैं—एक को 3 करोड़ का और दूसरी को 6.36 करोड़ का न्याय-निर्णायक की नियुक्ति हो चुकी है परन्तु 1960 से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 21 मामलों में अभी तक कोई कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बर्ड एन्ड कम्पनी का मामला यों ही पड़ा हुआ है। इस से स्पष्ट है कि वित्त मंत्री देश के लिये अधिक धन प्राप्त करने के लिये इच्छुक नहीं हैं।

हमें यह मानना पड़ेगा कि रुपये का मूल्य घट रहा है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरीका में रुपये का मूल्य 10 सट रह गया है। रुपये के मूल्य को मजबूत बनाया जाना चाहिये। मैं अवमूल्यन के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि ऐसा करना हमारे देश के हित में नहीं है। सरकार को अवमूल्यन के बारे में वास्तविकता को बताना चाहिये और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करन चाहिये।

विदेशी सहायता के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि प्रत्येक योजना के बाद हम विदेशी सहायता पर और अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये विदेशी सहायता आवश्यक है परन्तु विदेशी सहायता उपलब्ध करने के लिये हमें अपनी राजनीतिक तथा अन्य नीतियों को दूसरे के हाथों बेच नहीं देना चाहिये।

यद्यपि श्री अशोक मेहता ने कहा है कि अमेरीका में कोई राजनैतिक चर्चा नहीं हुई है परन्तु 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह छपा है कि वहां श्री एक के साथ पंजाबी सूबा तथा नागा समस्या आदि आन्तरिक विषयों के बारे में चर्चा की गई है। वह हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेशी सहायता के प्रतिकूल प्रभाव समाप्त किये जाने चाहिये।

मैं उर्वरकों सम्बन्धी समझौते के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह समझौते लम्बी अवधि के होने चाहिये। यदि हम अपने देश में किसी सरकारी उपक्रम में गैर सरकारी लोगों को अंशों की बहुसंख्या नहीं देना चाहते तो हम उर्वरक के मामले में अधिकांश अंश देने की अनुमति कैसे दे सकते है। विक्रय के मामले में भी उनका अधिक हाथ होगा। वे मूल्य के मामले में भी अपना हाथ चाहते हैं। हम अपने अधिकार ऐसे मामलों में छोड़ रहे हैं जिनमें साधारणतया दूसरों का कोई हाथ नहीं होना चाहिये।

शिक्षा संस्थान के विषय में देश के शिक्षा विशारद भी चिंतित हैं। वह यह अनुभव करते हैं कि इससे हमारे देश की शिक्षा सम्बन्धी समूची नीति का अतिक्रमण होगा। हम संस्थान के उद्देश्य विदेश, नियंत्रण और प्रबन्ध के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं। मेरा सुझाव यह है कि शिक्षा संस्थान का संविधान चाहे कुछ भी हो कम से कम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को ही इन संस्थान का अध्यक्ष बनाना चाहिये।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : यह दुख की बात है कि यह समाप्त होते ही मंत्री सरकार के आलोचक बन जाते हैं। यह विचित्र बात है कि सदस्य प्रशासन के उच्च स्तर पर सरकारी व्यय की आलोचना करते हैं और साथ ही इस बात पर जोर भी देते है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जायें जिन लोगों ने लोकतन्त्र के भविष्य के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लोकतन्त्र हमारे देश में स्थिर हो गया है और वह लगातार फलता फूलता रहेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि धन कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो रहा है और उसे रोका जाना चाहिये। स्वर्गीय श्री फीरोज गांधी ने सब से पहले यह प्रश्न उठाया था। इसकी जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। सरकार हमारी अर्थव्यवस्था की में इस प्रवृत्ति से अवगत है और इसको रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। हमें निर्वाह स्तर में वृद्धि के बारे से छुटकारा प्राप्त करना चाहिये।

कुछ समय पूर्व मैं वाशिंग्टन गया था। विश्व बैंक के प्रमुख अधिकरियों ने मुझे बताया है कि जापान में 25 प्रतिशत व्यय स्थापना पर तथा 75 प्रतिशत व्यय वास्तविक कार्य पर किया जाता है परन्तु भारत में इस से उलट ही होता है।

मैं श्री चटर्जी की स्वचलित यंत्र न लगाने की मांग का समर्थन करता हूं। मशीनों के आयात से हमारी कठिनाइयां बढेंगी।

अल्पसंख्यकों का प्रश्न उठाया गया है। मेरा विचार है कि संविधान बनने तथा व्यस्क मताधिकार मिलने के बाद हमारे देश में अल्पसंख्यकों की कोई समस्या नहीं है। उनकी समस्या उठाने वाले लोग किसी उद्देश्य के अन्तर्गत ही ऐसा करते हैं। हमें सीमाओं पर घुसपैठ के सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

चाहिये। सीमा की दूसरी ओर से लगातार छापे मारे जा रहे है और सीमा के निवासियों के जीवन में गड़बड़ी रहती है। गृह-कार्य मंत्री को विशेष रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिये। गृह-कार्य मंत्री को अश्लील लेख रोकने के लिए विशेष ध्यान रखाना चाहिये। प्रैस कौन्सिल बनने तक देश में इन अश्लील लेखों की भरमार रहेगी। यह युवकों तथा सामाजिक नैतिकता के लिए अधिकतर होगा।

पश्चिमी बंगाल में हलिदया तथा फरक्का दो परियोजनायें हैं। उनका कार्य जारी रखा जाना चाहिये और ठीक समय पर कार्य पूरा किया जाना चाहिये। मूल योजना में परिवर्तन नही किया जाना चाहिये।

शिक्षा संस्थाओं के द्वार खुले रहने चाहियें। हमारी शिक्षा संस्थाओ में विदेशों से इतनी बड़ी राशि आने से गांधीजी का सन्देह पूरा हो सकता है। विदेशी मित्रों से मेरी यह प्रार्थना है कि वह इस देश में अनुसन्धानशालायें स्थापित करें ताकि हमारे विद्यार्थियों के विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में न जाना पड़े। यदि ऐसा किया जाये तो हम उनके आभारी होंगे।

Shri Bal Krishna Singh(Chandanli) : Whatever the definition of socialistic society may be, the country wants removal of poverty, educational facilities, employment, residential accommodation, foodgrains and things of daily necessities. It is doubtful that the Finance Minister will be able to lead the country to socialism through budget proposals. But he has been able to give some relief to the people in spite of the imbalance created in our economy due to Pakistani and Chinese threats.

The prices are rising and it is bitting the people very badly. This is the immediate problem before the country. If we want to bring about a balance in our economy, it is necessary to pay greater attention to agriculture and agriculture-based industries. Nearly forty-six per cent of our national income comes from agriculture and 70 per cent of our population is dependent on agriculture. It can only be ignored at national risk. If food supply under P. L. 480 is stopped, there will be anarchy in the country. Therefore, agriculture should be given top priority, otherwise it is doubtful to balance the economic position of the country through this budget.

We want to increase the production. The youngmen of today are modernsied and they prefer tractor to plough and power-operated pumping sets to the old methods and so on. Therefore, we must give attraction to them by providing those facilities. Otherwise, a drift from the villages to cities will create serious problems. If iron electric poles are not available, wooden poles should be used for taking electricity to tne villages.

I feel that the Planning Commission has not taken steps in the right direction in the matter of formulating plans for the country. The commission has failed to narrow down regional disparities. A Committee was set up to look into the conditions in Eastern Uttar Pradesh. The Committee submitted its report but the central Government told the State Government that they should find resources themselves. Although Eastern Uttar Pradesh as played an important part in the fight for freedom, she has been ignored in the matter of economic development. I, therefore, request that separate plan should be formulated for the development of eastern Uttar Pradesh.

Educational planning is very necessary. It is the duty of educational institutions to provide good citizens. There should be a definite education policy for the whole country. The Government has failed even to state a clear policy with regard to Hindi which is our national language.

श्री यलमंदा रेड्डी (मरकापुर) : सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों इस देश के एकाधिकारियों तथा विदेशी एकाधिकारियों और भूस्वामियों को सहायता मिलती है। ऐसी सरकारी नीतियों के कारण देश की आर्थिक दशा बिगड़ गई है और हम चौथी योजना नहीं बना सकते हैं। विकास की दर अन्य देशों मे बहुत कम है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और निर्धन लोगों की दशा दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। थोड़े से व्यापारी बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। सरकार लोगों की सहायता के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही। सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे देश तथा लोगों को सहायता मिले।

मैंने कल समाचार पत्रों में पढ़ा है कि राजस्थान नहर के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकार की गई है परन्तु सरकार ने नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में कुछ नहीं सोचा है जिससे 25 लाख से 34 लाख एकड़ तक की सिंचाई हो सकती है। सरकार ने नागार्जुन सागर परियोजना के लिए 1966–67 के लिए 8.2 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। इस राशि से राज्य सरकार केवल जून अथवा जुलाई तक ही कार्य चला सकती है। इसके बाद वहां कार्य बंद करना होगा। सरकार को इस योजना के लिए 1966–67 में 10 करोड़ रुपये तुरन्त मंजूर करने चाहियें ताकि योजना इतनी पूरी हो जाये कि अन्न की उपज में तुरन्त वृद्धि करने के लिए 6 अथवा 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई तुरन्त हो सके।

सरकार ने रायलसीमा के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी कोई राशि मंजूर नहीं की है। आन्ध्र प्रदेश सरकार कम से कम $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये के ऋण की माग कर रही है। यह ऋण मंजूर किया जाना चाहिये ताकि रायलसीमा के अकाल ग्रस्त लोगों को कोई राहत मिल सके।

सीमेन्ट पर नियंत्रण हटाने से कारखानदारों को 27 करोड़ का लाभ हो सकेगा परन्तु वे श्रमिकों पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं, उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मछरेला नगर में सीमेंट कारखाने के श्रमिकों को बहुत सी कठिनाइयां हैं। सरकार तथा कारखाने के प्रबन्धकों को उन श्रमिकों की वास्तविक मांगें पूरी करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

हमारे राज्य में लगातार यह मांग की जा रही है कि रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जाये। मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि केन्द्रीय सरकार इसे अपने हाथ में ले ले। राज्य सरकार ने राजामुंद्री कागज़ कारखाने का राष्ट्रीयकरण समाप्त कर दिया है और उसे सोमानी परिवार को वापिस दे दिया है। आन्ध्र प्रदेश में बिड़ला परिवार के कई कारखाने हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करुंगा कि रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी को सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाना चाहिये क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसे बिड़ला परिवार को नहीं दिया जाना चाहिये।

विशाखापटनम में इस्पात कारखाने के बारे में सार्थ समूह का प्रतिवेदन पहले ही प्राप्त हो चुका है यद्यपि राज्य सरकार तथा आन्ध्र की जनता केन्द्रीय सरकार से पांचवां इस्पात कारखाना विशाखापटनम में लगाने की प्रार्थना कर रही है तथापि सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस सम्बन्ध में तुरन्त निर्णय लिया जाना चाहिये।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : देश के समक्ष विभिन्न समस्याओं से मुझे कोई चिन्ता की बात दिखाई नहीं देती। पराधीन रहने के कारण यह समस्यायें पैदा होने से हमें चिन्तित नहीं होना चाहिये। सरकार को उन पर गम्भीरता से विचार करने दृढ़ निर्णय करना चाहिये।

सरकार को राज्यों के बीच सीमा, पानी अथवा आर्थिक झगड़ों को सुलझाने के लिये अच्छी तरह सोच विचार के पश्चात् निश्चित निर्णय लेना चाहिये और फिर उस पर दृढ़ रहना चाहिये।

[श्री ओझा]

यह सच है कि तीसरी योजना में बहुत से लक्ष्यों को पूरा नही कर सके है। यह भी सच है कि हम कुछ क्षत्रों में असफल रहे हैं परन्तु कुछ क्षेत्रों में हमने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इसलिये मेरा कहना है कि हमें कुछ मामलों में असफलता से निराश नहीं होना चाहिये।

देश के विकास के लिये हमने योजना की जो नीति अपनाई है हमें उससे पीछे नही हटना चाहिये। इधर-उधर कुछ त्रुटियां हो सकती है परन्तु अब इतना आगे बढ़कर अथवा विकास करके पीछे हटने का कोई लाभ नही है। यदि हम अपनी योजनाओं को पूरा नहीं करते हैं तो हम होने वाले लाभ को खो देंगे। हमें चौथी योजना को उसी रूप में कार्यान्वित करना है जिस रूप में हमने उसे बनाया है। इसके पश्चात हमें पांचवीं योजना को भी कार्यान्वित करना होगा। हमारे अर्थ शास्त्रीयों का कहना है कि पांचवी योजना के अन्त तक हमारी अर्थव्यवस्था आत्मजनक हो जायेगी। श्री दांडेकर ने गैर-विकास सम्बन्धी खर्च का उल्लेख किया है। यह सच है कि यह खर्च बढ़ रहा है परन्तु इसे बढ़ना ही है क्योंकि आज जो खर्च विकास सम्बन्धी है कल वही खर्च गैर-विकासकारी हो जायेगा। हमने बहुत से अस्पताल, सड़कें तथा पुल बनाये हैं उनको बनाये रखने के लिये खर्च करना होगा। इस प्रकार यह खर्च गैर-विकासकारी हो जायेगा।

कुछ मित्रों ने विदेशी सहायता की कड़ी आलोचना की है। कोई भी अल्प-विकसित देश विकसित देशों की सहायता के बिना प्रगति नही कर सकता। सभी अल्प विकसित देशों को विकसित देशों से सहायता प्राप्त करनी पड़ती है। यदि विदेशी सहायता के साथ शर्तें न लगी हो तो हमें सहायता लेने से हिचकचाना नहीं चाहियें।

वित्त मंत्री ने करों के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय जिस साहस तथा बुद्धि का परिचय दिया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। कई वर्षों में प्रथम बार वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों की बजाय प्रत्यक्ष करों पर जोर दिया है।

सभी जानते है कि अप्रत्यक्ष कर बढ़ रहे है और इनका प्रभाव गरीब लोगों पर अधिक पड़ता है। हमारे जैसे अल्प-विकसित देश के लिये कई बार गरीब लोगों के ऊपर भी कर लगाना आवश्यक हो जाता है परन्तु उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिये। मेरा विचार है कि अप्रत्यक्ष करों के बारे में हमने अधिकतम सीमा प्राप्त कर ली है और हमें अधिक अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने चाहिये। मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस वर्ष अप्रत्यक्ष करों की बजाय प्रत्यक्ष करों पर जोर दिया है। प्रत्यक्ष करों के मामले में भी वित्त मंत्री ने भी बुद्धिमत्ता दिखाई है कि उन्होंने कम आय वाले वर्ग के लोगों को आयकर विभाग के आतंक से बचाया है।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि कानून को सरल बनाया जाना चाहिये ताकि सभी लोग समझ सके। परन्तु इतने जटिल समाज मे कानून को इतना सरल नहीं बनाया जा सकता परन्तु फिर भी हमे कानून को जितना सरल हो सके बनाना चाहिये। हमें कानून में इतने अधिक संशोधन भी नहीं करने चाहियें। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

नर्मदा नदी देश की बड़ी नदियों में से एक है। यह नदी तीन राज्यों में से गुजरती है। मेरा विचार है कि हमे नर्मदा परियोजना पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। सरकार ने यह मामला खोसला समिति को सौंप कर एक ठीक निर्णय लिया था। श्री खोसला किसी भी सम्बन्धित राज्य के रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने सभी तथ्यों की अच्छी प्रकार जांच करने के पश्चात एक प्रतिवेदन सरकार को दिया था। दुर्भाग्यवश इस परियोजना के बारे में कुछ कटुता उत्पन्न हो गई है। कुछ वर्गों में गलत-फहमी के कारण इस परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। इस परियोजना का बनाया जाना राष्ट्रीय हित में है इसलिये खोसला आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

मेरे क्षेत्र में 'ग्रे बोर्ड' बनाने वाले बहुत से छोटे छोटे एकक हैं। उनमें अधिकतर स्थानीय लोग ही काम करते हैं। हाल ही में एक अधिसूचना द्वारा 'ग्रे-बोर्ड' पर उत्पादन शुल्क में 300 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। अपने कल के भाषण में वित्त मंत्री ने कुछ रियायत दी है अर्थात उत्पादन शुल्क को 42 पैसे प्रति किलोग्राम से कम करके 28 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। परन्तु फिर भी मेरा निवेदन है कि इन छोटे एककों के मामले पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ही क्षेत्र में दो एकक बन्द हो गये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : 18 वर्ष की स्वतन्त्रता के पश्चात भी हमारे देश में प्रत्येक वस्तु की कमी है। हमारे देश में प्रत्येक मात्रा में मिलती थी परन्तु आज यह देश भिखमंगों का देश बन कर रह गया है। मंत्री लोग विदेशों में ईश्वर के नाम, लोकतन्त्र तथा समाजवाद के नाम भिक्षा मांगने जाते हैं।

आज जबकि हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे है देश के प्रत्येक राज्य में, बढ़ते हुए मूल्यों, भुखमरी, अकाल की स्थिति तथा सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्रों में मजदूरों को वेतन न मिलने के विरुद्ध जनता आन्दोलन कर रही है। सरकार जनता के इन आन्दोलनों को लाठी तथा गोली के बल पर दबा रही है। पिछले 18 वर्षों से यही होता आ रहा है।

प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वचनों तथा दूसरी बातों से हमने सोचा था कि सरकार आपात की स्थिति को समाप्त कर देगी और भारत रक्षा नियमों को वापिस ले लेगी। परन्तु कल गृह-कार्य मंत्री ने यह कह कर कि भारत रक्षा नियमों का सावधानी से प्रयोग किया जायेगा और कि आपात की स्थिति बनी रहेगी, लोगों की आशाओं पर पानी फर दिया है। हमारे देश लोकतन्त्र देश के लिये यह एक चिन्ता का विषय है। वह समय शीघ्र ही आनेवाला है जबकि देश की जनता आपात की स्थिति तथा भारत रक्षा नियमों का उल्लंघन करना आरम्भ कर देगी। इस लिये सरकार को यह महसूस करना चाहिये कि इस प्रकार की स्थिति को लम्बी अवधि के लिये नही बनाये रखा जा सकता।

देश के सामने बहुतसी समस्याएं हैं। वित्त मंत्री ने निम्न आय वर्ग के लोगों को कुछ रियायत दी है। जिसके लिये में उनको बधाई देता हूँ। परन्तु यदि करों में वृद्धि होती रही और मुद्रास्फीति की स्थिति तथा लोगो की बेचैनी में वृद्धि होती रही तो मैं नही कह सकता कि इस देश का क्या बनेगा।

देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। प्रत्येक वर्ष बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। मेरे चुनाव क्षेत्र कानपुर में पिछले दस महीनों से लगभग आठ हजार कर्मचारियों को कोई मजूरी अथवा भत्ता नहीं मिला है। कुछ अन्य मिलों के बन्द होने की भी सम्भावना है। मुझे समाचार पत्रों में यह पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंत्रिमण्डल ने म्यूर मिल को चलाने के लिये 80 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है। गैर-सरकारी मिलों के मालिकों के कुप्रबन्ध के कारण लगभग 30 से 40 हजार कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं और सरकार इन मिलो को अपने नियंत्रण में लेने में असफल रही है। मैं वित्त मंत्री को निवेदन करूंगा कि वह इन मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने की ओर ध्यान दें।

इस बात को जानते हुए भी कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है सरकार ने जीवन बीमा निगम में इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटरों को अमरीका से मंगाया है। इससे कई कर्मचारी फालतू हो जायेंगे। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह स्वयं इस मामले पर ध्यान दें और देखेंगे कि इन कम्प्यूटरों से रोजगार की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सर्वे आफ इन्डिया के कर्मचारियों की मांग पर ध्यान दें। इन कर्मचारियों ने चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान बहुत शानदार कार्य किया है। उनकी मांग केवल यह है कि अन्य विभागों में जो तुलनात्मक वेतन-क्रम है वहीं उनको भी दिये जाये। वे अपने वेतन क्रमों का पुनरीक्षण नहीं चाहते। इन लोगों को बड़ी कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पडता है इसलिये इनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

[श्री स० मो० बनर्जी]

देश भर में पेंशन लेने वालों ने सरकार से अपील की है कि उनके साथ न्याय किया जाये तथा जीवन निर्वाह की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखकर पेंशनों मे वृद्धि की जानी चाहिये। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इन लोगों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

विश्वविद्यालयों तथा कॉलेज के अध्यापकों को तो कुछ रियायतें दी गई हैं परन्तु प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों आदि में सुधार नही किया गया है। आम तौर पर सरकार यह कहती है कि वे राष्ट्र के निर्माता हैं। परन्तु जब उनको खाने को, पहनने को पर्याप्त नही मिलेगा तो वे राष्ट्र का निर्माण क्या करेंगे। उनको समाज में उचित स्थान दिया जाना चाहिये। उनको चपरासियों से भी कम वेतन मिल रहा है। इसलिये उनके वेतन-क्रमों में सुधार किया जाना चाहिये।

रेलवे तथा प्रतिरक्षा के कर्मचारियों ने एक मजूरी बोर्ड के स्थापित किये जाने की मांग की है। सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसा करने के लिये अभी उचित समय नहीं आया है। क्या सरकार यह चाहती है कि लोग आन्दोलन करें? औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि उद्योगों ये शान्ति बने रहे। इसलिये सरकार को उनकी मांग पर उचित ढंग से विचार करना चाहिये। वित मंत्री को यह बताना चाहिये कि क्या यह सच है कि कानपुर के एक उद्योगपति के 31 लाख रुपये के आयकर को बट्टे खाते डाल दिया गया है। क्या यह वही व्यक्ति है जिसने गोंडा से चुनाव लड़ा था और वह इस सभा के सदस्य थे? क्या यह वह व्यक्ति है जिस ने एक टुकड़ा भूमि अर्जित करने के लिये सरकार को मजबूर कर दिया था। वित्त मंत्री को इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करानी चाहिये।

श्री अरुणाचलम (रामनाथपुरम): आयकर से छूट की सीमा में प्रतिवर्ष 500 रुपये की और वृद्धि करने से कम आय वाले वर्ग के लोगों को सराहनीय रियायत मिली है। विकासशील अर्थव्यवस्था में करों के अतिरिक्त बोझ से कोई नहीं बच सकता तथा बलिदान किये बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। यदि जीवनस्तर को उचां उठाना है तथा देश को समृद्ध बनाना है तो बलिदान करना ही होगा। सभी लोगों को इन अस्थायी कठिनाइयों को सहन करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

विकास के हित के लिये यह आवश्यक है कि देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाये, जिससे लोग अधिक धन विकासकारी कार्यों में लगा सके। जो देश ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं भारत को उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिये।

भारत को कम से कम समय में कृषि उत्पादन में आत्म-निर्भर होने का यत्न करना चाहिये। कृषि को प्रतिरक्षा के समान उच्चतम प्राथमिकता देने सम्बन्धी नीति सराहनीय है। यह संतोष की बात है कि छोटी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक सुविधाओं को व्यवस्था करने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इस बारे मे में सरकार से अनुरोध करुंगा कि वे पानी के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने की ओर तुरन्त ध्यान दें। इस बारे में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि केरल मे काफी पानी बेकार जा रहा है। सरकार को सूझ-बूझ से कार्य करके केरल के फालतू पानी का मद्रास के कम पानी वाले क्षेत्रों मे उपयोग करना चाहिये जिस से इस क्षेत्र में पर्याप्त अनाज उत्पन्न हो सके तथा वह अनाज केरल को दिया जा सके। अन्तर्राज्जीय जल विवादों को हल करने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

बर्मा तथा लंका से आने वाले बहुत से लोग अनुभवी किसान है। यदि सरकार उनका उचित ढंग से पुनर्वास करे तो वे देश के लिये काफी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। यह सच है कि इनमें से अधिकांश लोग मद्रास, केरल और आंध्र प्रदेश मे रह रहे हैं और कि वहां पर फालतू भमि पर्याप्त नहीं है। परन्तु उनको मध्य प्रदेश तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में बसाया जा सकता है। यदि इन लोगों को वहां पर कृषि के लिये भमि दी जाती है तो ये लोग देश के लिये बहुत लाभकारी सिद्ध होंग। ऋण के रुप में उन्हें जो पुनर्वास-सहायता दी गई है उस से समस्या की गम्भीरता म कोई कमी नहीं आई है। सरकार को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिये।

श्री लंका से लौटाये जाने वाले भारतीयों की समस्या निरंतर बनी रहेगी क्योंकि निकट भविष्य में भी वहां से काफी लोग आयेंगे। इसलिये सरकार को उन्हें एक निश्चित ढंग से सुविधायें देने के लिये एकीकृत योजना बनानी चाहिये। इस समय किसानों को सुधरे हुए बीज, उर्वरक तथा औजार आदि देने की बहुत चर्चा है। यह सब तो ठीक है परन्तु इस समय सब से अधिक आवश्यकता पानी की है: जहां कहीं भी सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं वहां पर फसल अच्छी हुई है।

मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में बहुत किसान है परन्तु उनके सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप वहां के लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस क्षेत्र के किसानों को पानी नियमित रूप से मिलता रहे। सरकार को इस समस्त क्षत्र में नलकूप लगवाने चाहिये। यदि इस क्षेत्र को पानी की पर्याप्त सुविधाये दी जाये तो यहां पर चावल का उत्पादन काफी बढ़ सकता है।

इस बारे में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मद्रास सरकार तथा योजना आयोग ने पूर्वी रामनाथपुरम के क्षत्र को मद्रास राज्य में सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र बात है। मुझे प्रतीत हुआ है कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के ऐसे पूर्वी जिलो को, जो कि पिछड़े हुए हैं, विशष रियायत देती रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को पूर्वी रामनाथपुरम के क्षेत्र के लोगों के प्रति भी उदारता दिखानी चाहिये।

Shri Lahtan Chaudhry (Saharsa) : This is true that these plans have already been completed and the country has made much progress. But there is a category of persons in this country who have not derived any benefit from these plans. They are agriculture labours. According to 1956-57 report there are 57·1 per cent labourers are landless. In spite of that there are casual labourers who remain unemployed 128 days in a year.

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 3 मई, 1966/13 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई। *The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May* 3, 1966/ *Vaisakha* 13, 1888 (*Saka*).

मा०स०मु०ना०–वि० रा–67 लोक सभा/66–3-10-66–600